



संक्षिप्तवार्ता

सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत

नई दिल्ली। वीर सावरकर को लेकर कथित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर शिकायत और मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन आदेश को रद्द कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अभियोजन को आगे बढ़ाने के लिए यदि आवश्यक मंजूरी अनिवार्य है और वह उपलब्ध नहीं है, तो मामले की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे का भी संज्ञान लिया, जिसमें अभियोजन के लिए आवश्यक मंजूरी दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं था।

जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ी, एम्स में भर्ती

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि 13 अगस्त की शाम उन्हें बेचेनी महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया।

एम्स पहुंचने पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उनकी प्रारंभिक जांच की। स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का आकलन करने के लिए हृदय से जुड़े परीक्षण भी किए गए। इनमें हृदय की धमनियों की स्थिति की जांच के लिए एजियोग्राफी भी शामिल रही।

अस्पताल में नड्डा को एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में विशेष निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों की टीम उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यक चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत उपचार किया जा रहा है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। नड्डा के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए कई वरिष्ठ अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। चिकित्सा दल उनकी स्थिति की नियमित निगरानी कर रहा है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, फिलहाल किसी गंभीर स्थिति की जानकारी सामने नहीं आई है। डॉक्टर उनकी जांच रिपोर्ट और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर आगे के उपचार को लेकर निर्णय ले रहे हैं।

प्रसिद्ध इतिहासकार सुमित सरकार का निधन

नई दिल्ली। प्रसिद्ध इतिहासकार सुमित सरकार का दिल्ली स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। परिवार के करीबी लोगों के मुताबिक, वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनकी स्थिति हाल के दिनों में अधिक खराब हो गई थी। सुमित सरकार का जन्म 1939 में प्रसिद्ध इतिहासकार सुशोभन सरकार के परिवार में हुआ था। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास की पढ़ाई की। आधुनिक भारत के इतिहास पर उनके शोध और लेखन को व्यापक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।

अवकाश सूचना

15 अगस्त 2026 (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर कार्यालय में अवकाश रहेगा। अतः अंक 17 अगस्त 2026 को प्रकाशित होगा।

- संपादक

पीपलकोटी की निर्माणाधीन टनल में हादसा, 7 मजदूरों की मौत

वेब वार्ता, चमोली। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में अलकनंदा नदी पर निर्माणाधीन विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में गुरुवार शाम भूस्खलन और अचानक जल रिसाव से बड़ा हादसा हो गया। हादसे के वक्त टनल के भीतर काम कर रहे 22 मजदूर फंस गए। बचाव अभियान के दौरान सात मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 14 घायलों को जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती कराया गया है। तीन मजदूर अब भी लापता हैं।

प्रारंभिक जांचकारी के मुताबिक टनल के भीतर लूज क्षेत्र का एक हिस्सा अचानक



टूटकर नीचे आ गया। इसके साथ ही ऊपरी हिस्से में जमा पानी तेज बहाव के साथ टनल में घुस गया। मजदूरों को

संभलने का मौका तक नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई दी और उसके

बाद पानी व मलबा तेजी से अंदर आया। कुछ मजदूर इसकी चपेट में आ गए, जबकि कई अचानक आए पानी में फंस गए।

हादसे में घायल मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनके शरीर पर गंभीर घोटों के निशान हैं। पंजाब के तरनतारन निवासी 47 वर्षीय सबीर सिंह का जबड़ा टूट गया। उन्होंने बताया कि टनल अचानक टूटने के साथ तेज पानी अंदर आया और मजदूर डूबर-डूबर गिरने लगे। छत्तीसगढ़ के 20 वर्षीय सुनील दीवान ने बताया कि हादसे के समय मजदूर परियोजना की पीपलकोटी साइट में मौजूद थे और देखते ही देखते पानी भरने लगा। झारखंड के

मजदूरों ने भी अचानक धमाके जैसी आवाज सुनाई देने और तेज जलप्रवाह आने की जानकारी दी। एक घायल मजदूर के दोनों पैर मलबे की चपेट में आकर जखमी हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के घायल तिलक राज के अनुसार, टनल के करीब 1,800 मीटर बिंदु पर जलप्रवाह आया और इसी दौरान हादसा हुआ। पीपलकोटी की इसी परियोजना की सुरंग में पहले भी बड़ा हादसा हो चुका है। 130 दिसंबर 2025 को शिफ्ट बदलने के दौरान मजदूरों और कर्मचारियों को ले जा रही लोको ट्रेन की सामान ढोने वाली दूसरी लोको ट्रेन से टक्कर हो गई थी।

वेब वार्ता, नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित जांच समिति ने दिल्ली स्थित सरकारी आवास के स्टोर रूम में भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे तीनों आरोपों को सही पाया है। समिति की यह रिपोर्ट बुधवार को संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस वर्मा अपने आवास पर मिली नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत और स्वामित्व को लेकर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके अलावा, रिपोर्ट में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किए जाने का भी गंभीर जिक्र किया गया

है। चूंकि जस्टिस वर्मा अप्रैल 2026 में ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि क्या उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा और क्या उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इस पूरे प्रकरण ने भारतीय न्यायिक इतिहास के पुराने मामलों की यादें ताजा कर दी हैं। इससे पहले मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस सीएस कर्णन के मामले में एक हाईकोर्ट के जज को जेल जाने की नौबत आई थी, हालांकि उनका मामला भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि अदालत की अवमानना का था।

साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की गंभीर अवमानना के मामले में जस्टिस कर्णन को छह महीने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें कोयंबटूर से गिरफ्तार किया था। वह जेल जाने वाले देश के पहले मौजूदा हाईकोर्ट जज बने थे। हालांकि, जस्टिस वर्मा का मामला उससे अलग है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उनके सरकारी आवास से बरामद बेहिसाब नकदी और साक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। जस्टिस वर्मा के मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही को लेकर देश के जाने-माने कानूनी विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है।

सुबह 4 से 10 बजे तक कई रास्ते रहेंगे बंद



आवाजाही प्रभावित रहेगी। इसके अलावा राजघाट से आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड पर भी यातायात बंद रहेगा।

सी-हैक्सगान, इंडिया गेट, कोपरनिकस

जाने से बचने की सलाह दी गई है। सलीमगढ़ बाईपास से होकर गुजरने वाली आउटर रिंग रोड पर भी प्रतिबंध लागू रहेंगे। यात्रियों को परेशानी से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

उत्तर-दक्षिण दिशा में अरबिंदो मार्ग, सफ्दरजंग रोड, 11 मूर्ति, मदर टेरेसा क्रिसेंट, कमाल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, एसपी मार्ग, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां रोड और रानी झांसी रोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पूर्व से पश्चिम जाने वाले यात्रियों के लिए एनएच-24/एनएच-9, निजामुद्दीन खट्टा, बारापुल्ला रोड और रिंग रोड के रास्ते उपलब्ध रहेंगे। डीएनडी, बारापुल्ला रोड और रिंग रोड भी विकल्प होंगे। ट्रांस-यमुना से उत्तरी दिल्ली जाने वाले यात्री पुराना रोड, जीटी रोड, युधिष्ठिर सेतु और आईएसबीटी कश्मीरी गेट मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे।

8वें वेतन के लिए अभी कर्मचारियों-पेंशनर्स को करना होगा इंतजार

नई दिल्ली। करीब 70 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर टिकी हैं। आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हो चुका है, लेकिन अभी तक उसने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि संशोधित वेतन, भत्तों और पेंशन की रूपरेखा अभी तय नहीं हुई है। इसके साथ ही नई वेतन-पेंशन व्यवस्था लागू होने की तारीख भी घोषित नहीं की गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अभी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत

नहीं कर पाया है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन, महंगाई भत्ता (डीए), अन्य भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों में संभावित बदलाव के लिए आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा।

सरकार के मुताबिक, आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं। इस हिसाब से रिपोर्ट पेश करने की अंतिम समय-सीमा मई 2027 तक है। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आयोग की सिफारिशें लागू कब से होंगी। यही वजह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच संशोधित वेतन और पेंशन की प्रभावी

तारीख को लेकर असमंजस बना हुआ है।

8वें वेतन आयोग के दायरे में करीब 35.77 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 33.76 लाख पेंशनर्स आते हैं। रक्षा पेंशनभोगियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। पेंशनभोगी संगठन आयोग के सामने अपनी मांगें रख रहे हैं। इनमें महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) में हर तीन महीने पर संशोधन की मांग प्रमुख है। मौजूदा व्यवस्था में डीए और डीआर में साल में दो बार बदलाव होता है। मांग है कि बढ़ती महंगाई के असर को देखते हुए तिमाही आधार पर संशोधन किया जाए।

घर में एलपीजी सिलेंडर के नियम: दो से ज्यादा पर जुर्माना

वेब वार्ता, नई दिल्ली। क्या आपके घर में एक से ज्यादा गैस सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें एक रिजर्व के तौर पर रखा हुआ है? यह स्थिति कई लोगों के लिए सामान्य बात है, लेकिन इससे जुड़े कुछ जरूरी नियम हैं जिनकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। खासकर इस समय में जब मिडिल ईस्ट संकट के बाद एलपीजी और डबल सिलेंडर कनेक्शन को लेकर पहले लगी पाबंदियों में राहत दी गई है और अब इसतरह के आवेदनों को मंजूरी मिल रही है। आमतौर पर, घरेलू एलपीजी कनेक्शन में दो सिलेंडर रखने की अनुमति होती है, एक सिलेंडर खाना पकाने के लिए और दूसरा आपातकालीन स्थिति के लिए रिजर्व में रखा जाता है। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए है ताकि एक सिलेंडर खत्म होने पर तुरंत दूसरे का इस्तेमाल कर सके। हालांकि, घर में जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा करना नियमों के खिलाफ जा सकता है। रिपोर्टर्स के अनुसार, यदि आप दो से अधिक भरे हुए एलपीजी सिलेंडर घर में रखते हैं, तब इसके लिए संबंधित अधिकारियों से विशेष अनुमति लेनी पड़ सकती है।

भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती शुरू करने की मांग पोखरा में गोरखा के पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन

वेब वार्ता, पोखरा। नेपाल के पोखरा में पूर्व गोरखा सैनिकों और उनके समर्थकों ने भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती फिर शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने अग्निपथ योजना के तहत नेपाली युवाओं की भर्ती प्रक्रिया तत्काल बहाल करने की मांग की। यह प्रदर्शन भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ के 16 अगस्त से शुरू होने वाले पांच



दिवसीय नेपाल दौरे से कुछ दिन पहले हुआ। प्रदर्शन का आयोजन इंडियन एक्स-सर्विसमेन गोरखा ब्रिगेड नेपाल पोखरा की ओर से किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिला

प्रशासन कार्यालय के माध्यम से नेपाल सरकार को दो सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इसमें भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती तत्काल शुरू करने और सोल्जर शब्द वाले पूर्व सैनिक

संगठनों के नवीकरण की मांग की गई।

ब्रिगेड के अध्यक्ष कर्नल कृष्ण बहादुर खत्री ने कहा कि सुगौली संधि के बाद से 207 वर्षों से अधिक समय से नेपाली युवाओं की भारतीय सेना में भर्ती होती रही है। उनके मुताबिक अग्निपथ योजना लागू होने के बाद नेपाल सरकार ने विभिन्न कारणों से भर्ती प्रक्रिया रोक दी। इससे युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित होने के साथ गोरखा सैनिकों की पीढ़ियों पुरानी परंपरा पर भी संकट खड़ा हो गया है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि

भारतीय सेना में सेवा नेपाली युवाओं के लिए रोजगार का बेहतर विकल्प है। उनका दावा है कि अग्निपथ के तहत चार वर्ष की सेवा के दौरान युवा करीब 45 से 50 लाख रुपये तक कमा सकते हैं।

जारी रहेगा आन्दोलन

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह खाड़ी देशों में कठिन परिस्थितियों और कम वेतन पर काम करने की तुलना में बेहतर अवसर है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।

जस्टिस यशवंत वर्मा की क्या बढ़ जाएंगी मुश्किलें?

रिपोर्ट में आरोपों को बताया जा चुका है सही

वेब वार्ता, नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित जांच समिति ने दिल्ली स्थित सरकारी आवास के स्टोर रूम में भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे तीनों आरोपों को सही पाया है। समिति की यह रिपोर्ट बुधवार को संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस वर्मा अपने आवास पर मिली नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत और स्वामित्व को लेकर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके अलावा, रिपोर्ट में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किए जाने का भी गंभीर जिक्र किया गया

संपादकीय वी डोट केयर संसद

राहुल गांधी और अमित शाह बुनियादी तौर पर दोनों लोकसभा सांसद हैं। चूंकि राहुल विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के संसदीय दल के नेता हैं, लिहाजा वह नती प्रतिपक्ष तब किया गया है। अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के सदस्य हैं और उन्हें गृहमंत्री का दायित्व सौंपा गया है। दोनों ही नेता संसद से सुप्रीम नहीं हैं और न ही लोकसभा उनकी बपौती है। दोनों ही संसद के प्रति जवाबदेह हैं और नियम–प्रक्रिया से बंधे हैं। दिल्ली में छात्र, युवा आंदोलन के बाद गृहमंत्री अमित शाह संसद में दिखाई नहीं दिए। संसद भवन के अपने चैबर में उपस्थित रहना और सदन में मौजूदगी बिल्कुल विपरीत स्थितियां हैं। गृहमंत्री को दोनों सदनों में बयान देकर आंदोलन के दौरान, उसके बाद और प्रदर्शनकारियों पर बर्बर हमलों को लेकर पहले ही स्पष्टीकरण देना चाहिए था। यह उनका संवैधानिक दायित्व था। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष यह मांग लगातार करता रहा कि गृहमंत्री सदन में आएँ और बलाक़ि पैलेट गन क्यों चलाई गई? कीलों वाली लाठियां क्यों भांजी गई? किसने आदेश दिया था? गृहमंत्री के लिए गायक, लापता, भगोड़े, भाग गए सरीखे शब्द विपक्ष ने इसीलिए इस्तेमाल किए, क्योंकि न तो गृहमंत्री सामने आए और न ही बयान दिया। इन अमर्यादित, असंसदीय शब्दों की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। नतीजा यह हुआ कि संसद की कार्यवाही निरंतर स्थगित होती रही। मॉनसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और बुधवार, 12 अगस्त, तक 18 दिनों की बैठकें हुईं, लेकिन लोकसभा में कुल 17 घंटे भी काम नहीं किया जा सका। विपक्ष के हंगामे, शोर, नारेबाजी के बीच ही 59 मिनट में 9 बिल ध्वनि–मत से पारित करने पड़े। हरेक बिल पर औसतन 3–5 मिनट खर्च किए गए और किसी भी बिल पर कोई चर्चा नहीं की गई। राज्यसभा में भी क़रीब 31 फ़ीसदी काम किया जा सका। इन 18 दिनों में देश के करदाताओं के 118 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पर पानी फेर दिया गया, जबकि सांसदों के भत्ते अलग खर्च हैं। क्या इसी तरह देश का पैसा फूंकने और बिना चर्चा के बिल पारित करने को ही संसद बनी है? यहाँ यह भी प्रसंगिक है कि हमारी संसद अब साल में औसतन 50–65 दिन ही जुटती है और उस दौरान भी हंगामा मचा रहता है। अमरीका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों में संसद साल में 140–160 दिन काम करती है। यह तुलना हमारे अधिकतर माननीय नहीं जानते होंगे। बहरहाल जब मॉनसून सत्र साइनेड्राई (अनिश्चित रूप के लिए स्थगित) होने को आया, तो गृहमंत्री अमित शाह सामने आए और हर सवाल का जवाब देने की बात कही। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब सदन में हंगामा मच रहा था, कार्यवाही लगातार स्थगित करनी पड़ रही थी, तो वह सदन में आकर क्या करते? यहाँ हमारा सवाल भी है कि क्या गृहमंत्री हंगामे, नारेबाजी के बीच सदन में कभी भी नहीं गए? क्या शोर–शराबे में ही उन्होंने अपनी बात नहीं रखी? अनुच्छेद 370 खत्म किया जा रहा था, तो सदन में विपक्ष ने कितना शोर मचाया था? क्या गृहमंत्री ने अपना प्रस्ताव नहीं पढ़ा? बहरहाल जब गृहमंत्री विस्तृत और बिंदुवार बहस और जवाबदेही को तैयार हुए, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा–गृहमंत्री का लेकर सुनने में हमारी संसद दिलचस्पी नहीं। वह क्या बोलेंगे, वी डोट केयर (हमें उसकी परवाह नहीं)। वह पैलेट गन और लाठीचार्ज पर सीधा जवाब दें। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने गृहमंत्री के इस्तीफ़े का रग अलगपाया शुरू कर दिया। यदि पैलेट और लाठीचार्ज का आदेश गृहमंत्री ने दिया अथवा किसी और ने दिया और गृहमंत्री को उसकी जानकारी नहीं थी या बर्बर हमले का जिम्मेदार कोई भी हो, गृहमंत्री उसके लिए इस्तीफ़ा दें। क्या संसद की कार्यवाही और प्रणाली यही है? गृहमंत्री के वक्तव्य का विरोध करना और बस एक जवाब ही सुनना, यह राहुल गांधी की जिद और अहंकार हो सकता है। सदन की प्रक्रिया तो स्पीकर तय करते हैं। उस संदर्भ में कार्य मंत्रणा समिति (बीएससी) में गिगिय लिया जाता है, जिसमें लाभग्रा सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि होते हैं। गृहमंत्री से भी अपेक्षा थी कि विपक्ष सुनता या गैर–हाज़िर रहता अथवा हंगामा मचता रहता, उन्हें अपना वक्तव्य देना चाहिए था, ताकि वह संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता। यही देशहित था। संसद में केवल मंत्रणापेजी हो और जनहित के मसलों पर कोई चर्चा ही न हो, तो यह लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनाएगा। हर सियासी दल के सांसदों को जनता के मसले संसद में उठाने चाहिए तथा सरकार पर उनके समाधान के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए। तभी लोकतंत्र मजबूत होगा।

अमित शाह और राहुल गांधी

भारत का स्वतंत्रता संग्राम सही मायने में भारतीय समाज के आत्मसम्मान, अधिकारों और स्वशासन की आकांक्षाओं का व्यापक संघर्ष था। लगागम दो शताब्दियों के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अलग-अलग क्षेत्रों, संप्रदायों, वर्गों और विचारधाराओं के लोगों ने संघर्ष किया। इस लंबे आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मंच उपलब्ध कराया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे जन-आंदोलन का स्वरूप देने में निर्णायक भूमिका निभाई।

अमृतकाल में प्रथम बार

15 अगस्त

15 अगस्त, 1947

किसी भी देश का राष्ट्र ध्वज उसके स्वतंत्र होने का संकेत है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा केवल एक कपड़े या कपड़ का टुकड़ा नहीं है बल्कि यह भारत की आत्मा, इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। इसके तीन रंग केसरिया, सफ़ेद, हरा और मध्य में अशोक चक्र भारतीयता के विभिन्न धर्मों को दर्शाते हैं। तिरंगा न केवल स्वतंत्रता संग्राम की गाथा को बतलाता है, बल्कि यह भारत की एकता, विविधता और आकांक्षाओं की भी प्रतीक है। तिरंगे ने अपने रंगों से दुनिया में अपनी अद्वितीय छवि बनाई है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए हथकरघा खादी (सूती या रेशमी) कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तिरंगे झंडे में नीले रंग का अशोक चक्र धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है।

तिरंगे का केसरिया रंग साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक है। यह उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की अहुति दी। भारतीयता का यह पहलू हमें निःस्वार्थ भाव से देश के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देता है। इसी तरह से सफ़ेद रंग शान्ति और सत्य का प्रतीक यह रंग भारत की अहिंसावादी विचारधारा को रेखांकित करता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा और सत्याग्रह ने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि विश्व को शांति का संदेश भी दिया। यह रंग भारतीयता की उस भावना को दर्शाता है जो सहिष्णुता और सामंजस्य में विश्वास रखती है। हरी रंग समृद्धि, उर्वरता और प्रकृति के प्रति भारत की गहरी आस्था को दर्शाता है। भारत की संस्कृति में प्रकृति और

पर्यावरण का विशेष स्थान रहा है। यह रंग हमें सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देता है। मध्य में नीले रंग का अशोक चक्र गतिशीलता और प्रगति का प्रतीक है। यह सम्राट अशोक के धर्म चक्र से प्रेरित है जो न्याय, धर्म और नैतिकता का प्रतीक है। यह चक्र भारतीयता के उस दर्शन को दर्शाता है जो निरंतर प्रगति और नैतिकता के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। भारतीयता एक ऐसी अवधारणा है जो भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विविधता को समेटे हुए है। तिरंगा इस भारतीयता का एक जीवंत प्रतीक है।

भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। तिरंगा इस विविधता को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। जैसे तिरंगे के तीन रंग एक साथ मिलकर एक पूर्ण ध्वज बनाते हैं वैसे ही भारत की विभिन्न संस्कृतियों और समुदाय एक साथ मिलकर भारतीयता का निर्माण करते हैं। यह ध्वज हमें सिखाता है कि भिन्नताओं के बावजूद हम एक हैं। तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी रहा है। यह उन असंख्य बलिदानों का प्रतीक है जिन्होंने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाई। भारतीयता का यह पहलू हमें स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की भावना से जोड़ता है। तिरंगा हमें याद दिलाता है कि हमारी स्वतंत्रता अनमोल है और इसे बनाए रखने के लिए हमें सतत प्रयास करना होगा।

भारतीय इतिहास में 1905 से पहले पूरे भारत की अखंडता को दर्शाने के लिए कोई राष्ट्र ध्वज नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1905 में स्वामी

विवेकानंद की शिष्य सिरटर निवेदिता ने पहली बार पूरे भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना की थी। सिरटर निवेदिता द्वारा बनाए गए ध्वज में कुल 108 ज्योतिर्यों बनाई गई थीं। यह ध्वज चौकोर आकार का था। ध्वज के दो रंग – लाल और पीला। लाल रंग स्वतंत्रता संग्राम और पीला रंग विजय का प्रतीक था। ध्वज पर बंगाली भाषा में वंदे–मातरम् लिखा गया था और इसके पास वक्र (एक पत्रिका का हथियार) और केन्द्र में एक सफेद कमल का चित्र भी था। वर्तमान में इस ध्वज को आचार्य भवन सहायवास, कोलकाता में संरक्षित रखा गया है। इसके बाद 7 अगस्त 1906 को कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) के पारसी बागान चौक में ध्वज को फहराया गया। कोलकाता ध्वज प्रथम भारतीय अनाधिकारिक ध्वज था। इसकी अधिकल्पना शचिन्द्र प्रसाद बोस ने की थी। झंडे में बराबर चौड़ाई की तीन क्षैतिज पट्टियाँ थीं। शीर्ष धारी नारंगी, केंद्र धारी पीली और निचली पट्टी हरे रंग की थी। शीर्ष पट्टी पर ब्रिटिश–शासित भारत के आठ प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते 8 आधे खुले कमल के फूल थे और निचली पट्टी पर बाईं तरफ सूर्य और दाईं तरफ एक वर्धमान चंद्र की तस्वीर अंकित थी। ध्वज के केंद्र में वन्दे–मातरम् का नारा अंकित किया गया था। इसी तरह पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज मैडम श्रीकांजी कामा द्वारा 22 अगस्त 1907 को अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस इंडेंडेंटाग में फहराया गया था। इस ध्वज को सर्वाभि चंद्रकांत के नाम से जाना जाता है। यह ध्वज काफ़ी कुछबूझ 1906 के झंडे जैसा ही था लेकिन अक्सर सबसे ऊपरी पट्टी का रंग केसरिया था और कमल के बजाए

सात तारे सम्मरूपि के प्रतीक थे।

भारतीय धरती पर तीसरे प्रकार का तिरंगा होम रूल लीग के दौरान फहराया गया था। ज़्झोम रूल आंदोलनह्व के दौरान कोलकाता में एक कांग्रेस अधिवेशन के दौरान यह ध्वज फहराया गया था। उस समय ध्वज स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का प्रतीक था। इसमें 9 पट्टियाँ थीं, जिसमें 5 लाल रंग और 4 हरे रंग की थीं। ध्वज के ऊपरी बाएँ कोने में युनियन जैक था। शीर्ष दाएँ कोने में अर्धचंद्र और सितारा था। ध्वज के बाकी हिस्सों में सर्षाँ के स्वरूप में सात सितारों को व्यवस्थित किया गया था। वर्ष 1921 में आंध्र प्रदेश के पिंगली वैकड्या ने बिजावाड़ा (अब विजयवाड़ा) में गांधीजी के निर्देशों के अनुसार सफेद,हरे और लाल रंग में पहला चरखा–झंडा डिजाइन किया था।इस ध्वज को स्वरान–झंडे के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1931 ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। इस वर्ष तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह ध्वज जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चक्ते हुए चरखे के सरिया था।

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा के बाद भारतीय नेताओं को स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता का एहसास हुआ।

1947 में तिरंगा ध्वज

तदनुसार ध्वज को अंतिम रूप देने के लिए एक तदर्थ ध्वज समिति का गठन किया गया। सुरैया बद्र-उद-दीन तैयब द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को 17 जुलाई 1947 को ध्वज समिति द्वारा अनुमोदित और स्वीकार किया गया था। समिति की

सिफारिश पर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। तिरंगे में तीन समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ हैं जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पीछे धर्म क के साथ शांति और सत्य का संकेत है और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के विकास और उर्वरता को दर्शाती है। तिरंगे के केंद्र में सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। यह चक्र एक दिन के 24 घंटों और हमारे देश की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। तिरंगे को भारत की महिलाओं की ओर से 14 अगस्त, 1947 को संविधान सभा के अर्द्ध-रात्रिकालीन अधिवेशन में समर्पित किया गया था। भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी, 1950 को अपनाया था। भारत के तिरंगे झंडे के ध्वज की चौड़ाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। भारत का राज चिन्ह अशोक स्तम्भ के शीर्ष की एकता का घोतक है। राष्ट्रीय चिन्ह के दो भाग शीर्ष और आधार हैं। शीर्ष पर शेर दो आस और शक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह के आधार भाग में एक धर्म चक्र है। चक्र के दायी और एक बैल है तथा बायीं ओर एक घोड़ा है जो स्फूर्ति का ताकत

व गति का। हासत्यमेव जयतेह्व मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हासत्यमेव जयतेह्व का अर्थ सत्य की ही विजय अपनाया। तिरंगे में तीन समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ 1947 को अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 2002 से पहला कद बदल गया है। भारतीयों को कहीं भी किसी भी समय ध्वज के साथ झंडा फहराने की आजादी दे दी गयी है। अभी कुछ समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद दशाती है। तिरंगे के केंद्र में सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। यह चक्र एक दिन के 24 घंटों और हमारे देश की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। तिरंगे को भारत की महिलाओं की ओर से 14 अगस्त, 1947 को संविधान सभा के अर्द्ध-रात्रिकालीन अधिवेशन में समर्पित किया गया था। भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी, 1950 को अपनाया था। भारत के तिरंगे झंडे के ध्वज की चौड़ाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। भारत का राज चिन्ह अशोक स्तम्भ के शीर्ष की एकता का घोतक है। राष्ट्रीय चिन्ह के दो भाग शीर्ष और आधार हैं। शीर्ष पर शेर दो आस और शक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह के आधार भाग में एक धर्म चक्र है। चक्र के दायी और एक बैल है तथा बायीं ओर एक घोड़ा है जो स्फूर्ति का ताकत

व गति का। हासत्यमेव जयतेह्व मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हासत्यमेव जयतेह्व का अर्थ सत्य की ही विजय अपनाया। तिरंगे में तीन समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ 1947 को अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 2002 से पहला कद बदल गया है। भारतीयों को कहीं भी किसी भी समय ध्वज के साथ झंडा फहराने की आजादी दे दी गयी है। अभी कुछ समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद दशाती है। तिरंगे के केंद्र में सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। यह चक्र एक दिन के 24 घंटों और हमारे देश की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। तिरंगे को भारत की महिलाओं की ओर से 14 अगस्त, 1947 को संविधान सभा के अर्द्ध-रात्रिकालीन अधिवेशन में समर्पित किया गया था। भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी, 1950 को अपनाया था। भारत के तिरंगे झंडे के ध्वज की चौड़ाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। भारत का राज चिन्ह अशोक स्तम्भ के शीर्ष की एकता का घोतक है। राष्ट्रीय चिन्ह के दो भाग शीर्ष और आधार हैं। शीर्ष पर शेर दो आस और शक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह के आधार भाग में एक धर्म चक्र है। चक्र के दायी और एक बैल है तथा बायीं ओर एक घोड़ा है जो स्फूर्ति का ताकत

भारत का स्वतंत्रता संग्राम सही मायने में भारतीय समाज के आत्मसम्मान, अधिकारों और स्वशासन की आकांक्षाओं का व्यापक संघर्ष था। लगागम दो शताब्दियों के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अलग-अलग क्षेत्रों, संप्रदायों, वर्गों और विचारधाराओं के लोगों ने संघर्ष किया। इस लंबे आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मंच उपलब्ध कराया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे जन-आंदोलन का स्वरूप देने में निर्णायक भूमिका निभाई।

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीयों को अपनी राजनीतिक मांगों को संगठित रूप से उठाने का मंच मिला। प्रारंभिक दौर में दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश शासन की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों का विरोध किया। दादाभाई नौरोजी ने ह्दधन निकासी सिद्धांतह्व के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि औपनिवेशिक शासन भारत की संपदा को किस प्रकार बाहर ले जा रहा है। बीसवीं सदी में स्वतंत्रता आंदोलन ने नया मोड़ लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस व्यापक जनभागीदारी वाली शक्ति बनी। गांधी ने सत्य और अहिंसा को राजनीतिक संघर्ष का हथियार बना। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिला आंदोलन ने किसानों और श्रमिकों के बीच उभरती लड़ाई लड़कर कांग्रेस नेतृत्व को स्थापित किया। इसके बाद असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव को चुनौती दी। महात्मा गांधी का तब सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने स्वतंत्रता

भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल सत्ता परिवर्तन नहीं

15 अगस्त, 1947

के प्रश्न को आम भारतीयों के जीवन और अधिकारों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन को आधुनिक, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक दृष्टि देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे युवाओं और किसानों के बीच लोकप्रिय थे। पूर्ण स्वराज के प्रबल समर्थक बने। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। नेहरू ने जेल यात्राओं और आंदोलनों के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध किया। स्वतंत्र भारत के लिए लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच की मजबूत आधारभूमि तैयार की।

स्वतंत्रता संग्राम में केवल कांग्रेस और उसके प्रमुख नेताओं का ही योगदान नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया। सरदार वल्लभभाई पटेल ने किसान आंदोलनों और कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने का काम किया। स्वतंत्रता आंदोलन

को समाज के हर वर्ग से जोड़ दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने राष्ट्रीय एकता और हिंदू-मुस्लिम एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने साहस और बलिदान से युवाओं में राष्ट्रीय चेतना पैदा की। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता और कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसी आंदोलनरत महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। बड़ी संख्या में महिलाओं को भी इस जन आंदोलन से जोड़ा। भारत की आजादी किसी एक नेता, संगठन या आंदोलन का परिणाम नहीं थी। यह वर्षों तक चले राजनीतिक संघर्ष, जनआंदोलनों, क्रांतिकारी गतिविधियों, सामाजिक जागरण और असंख्य ज्ञात-अज्ञात सेनानियों के त्याग का परिणाम 15 अगस्त 1947 की आजादी थी। कांग्रेस ने राजनीतिक मंच दिया, गांधी ने आंदोलन को जनशक्ति और नैतिक आधार प्रदान किया, नेहरू ने आधुनिक भारत की कल्पना को दिशा दी, लाखों सेनानियों ने अपने संघर्ष और जान माल के बलिदान से स्वतंत्रता की कीमत चुकाई। इसी सामूहिक प्रयास ने 15

अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। भारत में पहली बार सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार मिला। सभी को समान अधिकार मिले। पहली बार भारत में लिखित संविधान के माध्यम से नागरिकों को मौलिक अधिकार के साथ जीने का अधिकार मिला। अब इस अधिकार को सुरक्षित बनाए रखने की जिम्मेदारी समस्त नागरिकों की है। देश के आजाद होने बाद पहली बार भारत के नागरिकों ने धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अनुभव किया। इस आजादी को कायम रखना नागरिकों की ही जिम्मेदारी है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं, उनमें कभी-कभी निरंकुशता और निरंकारी होने का भाव और कर्तव्य को लेकर हम जो भूल चुके थे उसे याद दिलाया है। डर, भय और लालच के साए में रहने लगे थे, युवाओं ने हमें नया रास्ता दिखा दिया है।

लेखक- सोरभ जैन अंकित

भारत का स्वतंत्रता संग्राम सही मायने में भारतीय समाज के आत्मसम्मान, अधिकारों और स्वशासन की आकांक्षाओं का व्यापक संघर्ष था। लगागम दो शताब्दियों के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अलग-अलग क्षेत्रों, संप्रदायों, वर्गों और विचारधाराओं के लोगों ने संघर्ष किया। इस लंबे आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मंच उपलब्ध कराया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे जन-आंदोलन का स्वरूप देने में निर्णायक भूमिका निभाई।

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीयों को अपनी राजनीतिक मांगों को संगठित रूप से उठाने का मंच मिला। प्रारंभिक दौर में दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश शासन की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों का विरोध किया। दादाभाई नौरोजी ने ह्दधन निकासी सिद्धांतह्व के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि औपनिवेशिक शासन भारत की संपदा को किस प्रकार बाहर ले जा रहा है। बीसवीं सदी में स्वतंत्रता आंदोलन ने नया मोड़ लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस व्यापक जनभागीदारी वाली शक्ति बनी। गांधी ने सत्य और अहिंसा को राजनीतिक संघर्ष का हथियार बना। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिला आंदोलन ने किसानों और श्रमिकों के बीच उभरती लड़ाई लड़कर कांग्रेस नेतृत्व को स्थापित किया। इसके बाद असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव को चुनौती दी। महात्मा गांधी का तब सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने स्वतंत्रता

को समाज के हर वर्ग से जोड़ दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने राष्ट्रीय एकता और हिंदू-मुस्लिम एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने साहस और बलिदान से युवाओं में राष्ट्रीय चेतना पैदा की। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता और कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसी आंदोलनरत महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। बड़ी संख्या में महिलाओं को भी इस जन आंदोलन से जोड़ा। भारत की आजादी किसी एक नेता, संगठन या आंदोलन का परिणाम नहीं थी। यह वर्षों तक चले राजनीतिक संघर्ष, जनआंदोलनों, क्रांतिकारी गतिविधियों, सामाजिक जागरण और असंख्य ज्ञात-अज्ञात सेनानियों के त्याग का परिणाम 15 अगस्त 1947 की आजादी थी। कांग्रेस ने राजनीतिक मंच दिया, गांधी ने आंदोलन को जनशक्ति और नैतिक आधार प्रदान किया, नेहरू ने आधुनिक भारत की कल्पना को दिशा दी, लाखों सेनानियों ने अपने संघर्ष और जान माल के बलिदान से स्वतंत्रता की कीमत चुकाई। इसी सामूहिक प्रयास ने 15

अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। भारत में पहली बार सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार मिला। सभी को समान अधिकार मिले। पहली बार भारत में लिखित संविधान के माध्यम से नागरिकों को मौलिक अधिकार के साथ जीने का अधिकार मिला। अब इस अधिकार को सुरक्षित बनाए रखने की जिम्मेदारी समस्त नागरिकों की है। देश के आजाद होने बाद पहली बार भारत के नागरिकों ने धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अनुभव किया। इस आजादी को कायम रखना नागरिकों की ही जिम्मेदारी है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं, उनमें कभी-कभी निरंकुशता और निरंकारी होने का भाव और कर्तव्य को लेकर हम जो भूल चुके थे उसे याद दिलाया है। डर, भय और लालच के साए में रहने लगे थे, युवाओं ने हमें नया रास्ता दिखा दिया है।

अमृतकाल में प्रथम बार

भारत का स्वतंत्रता संग्राम सही मायने में भारतीय समाज के आत्मसम्मान, अधिकारों और स्वशासन की आकांक्षाओं का व्यापक संघर्ष था। लगागम दो शताब्दियों के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अलग-अलग क्षेत्रों, संप्रदायों, वर्गों और विचारधाराओं के लोगों ने संघर्ष किया। इस लंबे आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मंच उपलब्ध कराया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे जन-आंदोलन का स्वरूप देने में निर्णायक भूमिका निभाई।

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीयों को अपनी राजनीतिक मांगों को संगठित रूप से उठाने का मंच मिला। प्रारंभिक दौर में दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश शासन की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों का विरोध किया। दादाभाई नौरोजी ने ह्दधन निकासी सिद्धांतह्व के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि औपनिवेशिक शासन भारत की संपदा को किस प्रकार बाहर ले जा रहा है। बीसवीं सदी में स्वतंत्रता आंदोलन ने नया मोड़ लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस व्यापक जनभागीदारी वाली शक्ति बनी। गांधी ने सत्य और अहिंसा को राजनीतिक संघर्ष का हथियार बना। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिला आंदोलन ने किसानों और श्रमिकों के बीच उभरती लड़ाई लड़कर कांग्रेस नेतृत्व को स्थापित किया। इसके बाद असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव को चुनौती दी। महात्मा गांधी का तब सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने स्वतंत्रता

को समाज के हर वर्ग से जोड़ दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने राष्ट्रीय एकता और हिंदू-मुस्लिम एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने साहस और बलिदान से युवाओं में राष्ट्रीय चेतना पैदा की। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता और कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसी आंदोलनरत महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। बड़ी संख्या में महिलाओं को भी इस जन आंदोलन से जोड़ा। भारत की आजादी किसी एक नेता, संगठन या आंदोलन का परिणाम नहीं थी। यह वर्षों तक चले राजनीतिक संघर्ष, जनआंदोलनों, क्रांतिकारी गतिविधियों, सामाजिक जागरण और असंख्य ज्ञात-अज्ञात सेनानियों के त्याग का परिणाम 15 अगस्त 1947 की आजादी थी। कांग्रेस ने राजनीतिक मंच दिया, गांधी ने आंदोलन को जनशक्ति और नैतिक आधार प्रदान किया, नेहरू ने आधुनिक भारत की कल्पना को दिशा दी, लाखों सेनानियों ने अपने संघर्ष और जान माल के बलिदान से स्वतंत्रता की कीमत चुकाई। इसी सामूहिक प्रयास ने 15

अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। भारत में पहली बार सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार मिला। सभी को समान अधिकार मिले। पहली बार भारत में लिखित संविधान के माध्यम से नागरिकों को मौलिक अधिकार के साथ जीने का अधिकार मिला। अब इस अधिकार को सुरक्षित बनाए रखने की जिम्मेदारी समस्त नागरिकों की है। देश के आजाद होने बाद पहली बार भारत के नागरिकों ने धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अनुभव किया। इस आजादी को कायम रखना नागरिकों की ही जिम्मेदारी है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं, उनमें कभी-कभी निरंकुशता और निरंकारी होने का भाव और कर्तव्य को लेकर हम जो भूल चुके थे उसे याद दिलाया है। डर, भय और लालच के साए में रहने लगे थे, युवाओं ने हमें नया रास्ता दिखा दिया है।

अमृतकाल में प्रथम बार

भारत का स्वतंत्रता संग्राम सही मायने में भारतीय समाज के आत्मसम्मान, अधिकारों और स्वशासन की आकांक्षाओं का व्यापक संघर्ष था। लगागम दो शताब्दियों के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अलग-अलग क्षेत्रों, संप्रदायों, वर्गों और विचारधाराओं के लोगों ने संघर्ष किया। इस लंबे आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मंच उपलब्ध कराया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे जन-आंदोलन का स्वरूप देने में निर्णायक भूमिका निभाई।

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीयों को अपनी राजनीतिक मांगों को संगठित रूप से उठाने का मंच मिला। प्रारंभिक दौर में दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश शासन की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों का विरोध किया। दादाभाई नौरोजी ने ह्दधन निकासी सिद्धांतह्व के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि औपनिवेशिक शासन भारत की संपदा को किस प्रकार बाहर ले जा रहा है। बीसवीं सदी में स्वतंत्रता आंदोलन ने नया मोड़ लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस व्यापक जनभागीदारी वाली शक्ति बनी। गांधी ने सत्य और अहिंसा को राजनीतिक संघर्ष का हथियार बना। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिला आंदोलन ने किसानों और श्रमिकों के बीच उभरती लड़ाई लड़कर कांग्रेस नेतृत्व को स्थापित किया। इसके बाद असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव को चुनौती दी। महात्मा गांधी का तब सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने स्वतंत्रता

को समाज के हर वर्ग से जोड़ दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने राष्ट्रीय एकता और हिंदू-मुस्लिम एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने साहस और बलिदान से युवाओं में राष्ट्रीय चेतना पैदा की। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता और कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसी आंदोलनरत महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। बड़ी संख्या में महिलाओं को भी इस जन आंदोलन से जोड़ा। भारत की आजादी किसी एक नेता, संगठन या आंदोलन का परिणाम नहीं थी। यह वर्षों तक चले राजनीतिक संघर्ष, जनआंदोलनों, क्रांतिकारी गतिविधियों, सामाजिक जागरण और असंख्य ज्ञात-अज्ञात सेनानियों के त्याग का परिणाम 15 अगस्त 1947 की आजादी थी। कांग्रेस ने राजनीतिक मंच दिया, गांधी ने आंदोलन को जनशक्ति और नैतिक आधार प्रदान किया, नेहरू ने आधुनिक भारत की कल्पना को दिशा दी, लाखों सेनानियों ने अपने संघर्ष और जान माल के बलिदान से स्वतंत्रता की कीमत चुकाई। इसी सामूहिक प्रयास ने 15

अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। भारत में पहली बार सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार मिला। सभी को समान अधिकार मिले। पहली बार भारत में लिखित संविधान के माध्यम से नागरिकों को मौलिक अधिकार के साथ जीने का अधिकार मिला। अब इस अधिकार को सुरक्षित बनाए रखने की जिम्मेदारी समस्त नागरिकों की है। देश के आजाद होने बाद पहली बार भारत के नागरिकों ने धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अनुभव किया। इस आजादी को कायम रखना नागरिकों की ही जिम्मेदारी है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं, उनमें कभी-कभी निरंकुशता और निरंकारी होने का भाव और कर्तव्य को लेकर हम जो भूल चुके थे उसे याद दिलाया है। डर, भय और लालच के साए में रहने लगे थे, युवाओं ने हमें नया रास्ता दिखा दिया है।

भारत का स्वतंत्रता संग्राम सही मायने में भारतीय समाज के आत्मसम्मान, अधिकारों और स्वशासन की आकांक्षाओं का व्यापक संघर्ष था। लगागम दो शताब्दियों के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अलग-अलग क्षेत्रों, संप्रदायों, वर्गों और विचारधाराओं के लोगों ने संघर्ष किया। इस लंबे आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मंच उपलब्ध कराया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू,

संक्षिप्तवार्ता

पूर्वी दिल्ली में डीटीसी बस की चपेट में आने से आठवीं कक्षा की छात्रा की मौत

नई दिल्ली, 14 अगस्त (वेब वार्ता)। पूर्वी दिल्ली के न्यु अशोक नगर इलाके में शुक्रवार को डीटीसी बस की चपेट में आने से आठवीं कक्षा की एक छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पड़िता अपने चाचा के साथ स्कूटर पर स्कूल जा रही थी, तभी सुबह करीब आठ बजे एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने कहा कि उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बस चालक, 45 वर्षीय एस के मुराद को बाद में पकड़ लिया गया। वह दुर्घटना के बाद भाग गया था।

बिजली का बिल बढ़ा देगा झटका, 8 फीसदी तक बढ़ा पीपीएसी शुल्क

नई दिल्ली, 14 अगस्त (वेब वार्ता)। राजधानी में बिजली का बिल एक बार फिर झटका देने वाला है। जून माह के लिए बिल में बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) की बढ़ोतरी को डीईआरसी (दिल्ली विद्युत नियामक आयोग) ने मंजूरी दे दी है। इसके चलते दिल्ली की बिजली कंपनियां आने वाले बिल में ग्राहकों से अतिरिक्त 7 से 8 फीसदी पीपीएसी लेगी। कंपनियों ने मौजूदा पीपीएसी को बढ़ाकर 23 से 31 फीसदी तक किए जाने की मांग डीईआरसी के समक्ष रखी थी।

जानकारी के अनुसार पहले प्रत्येक तीन माह में पीपीएसी को लेकर डीईआरसी समीक्षा करती थी। लेकिन अब इसमें बदलाव कर प्रत्येक माह पीपीएसी को लेकर समीक्षा होती है। बीते जुलाई माह में तीनों प्रमुख बिजली कंपनियां ने डीईआरसी के समक्ष प्रस्ताव देकर बताया कि बिजली की खरीद पर उन्हें अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ रहा है। इसलिए पीपीएसी को बढ़ाने की अनुमति दी जाए। बीएचईएस राजधानी ने पीएपीसी शुल्क 31.64 फीसदी, बीएसईएस यमुना ने पीपीएसी शुल्क 24.02 फीसदी एवं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने शुल्क 23.71 फीसदी करने की मांग डीईआरसी के समक्ष रखी थी।

व्यापार महोत्सव में शामिल हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

कहा सरकार उनके परिश्रम के साथ मजबूती से खड़ी

नई दिल्ली, 14 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवार को भारत मंडपम में आयोजित भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 में शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि व्यापारी और उद्यमी देश की आर्थिक शक्ति मजबूत कर रहे हैं तथा दिल्ली सरकार उनके परिश्रम के साथ मजबूती से खड़ी है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ह्रस्वदेशीह्म आज आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास बन चुका है। व्यापारी, उद्यमी और एमएसएमई केवल कारोबार नहीं बढ़ा रहे, वे परिवारों की खुशहाली, युवाओं के रोजगार और भारत की आर्थिक शक्ति को मजबूत कर रहे हैं।



मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार भी उनके इस परिश्रम के साथ मजबूती से

लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 14 अगस्त (वेब वार्ता)। शाहदरा साइबर पुलिस स्टेशन ने लोन धोखाधड़ी के मामले में 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से दो मोबाइल फोन, दो सिम कार्ड और एक एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं।

दरअसल, दिल्ली के शाहदरा निवासी कृष्ण अवतार सहगल की शिकायत पर साइबर पुलिस स्टेशन शाहदरा में एफआईआर दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह बैंक लोन की प्रक्रिया कर रहे थे, तभी उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को लोन-प्रोसेसिंग अधिकारी बताया। फाइल, प्रोसेसिंग चार्ज और लोन मंजूरी के बहाने, कॉलर ने उनसे कई बार पैमेंट करवाए। बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि कॉलर का बैंक से कोई संबंध नहीं था और उसने धोखाधड़ी से उनसे 1 लाख 10 हजार रुपए टग लिए थे। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को

पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया।

जांच के दौरान इटावा के रहने वाले रवि कुमार (26) की पहचान की गई और उसे गाजियाबाद के वैशाली में उसके किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया। धोखाधड़ी वाली कॉल के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर उसके नाम पर रजिस्टर्ड पाए गए और वे दिल्ली में साइबर अपराध के एक अन्य मामले से भी जुड़ा था। पृष्ठताछ के दौरान उसने बताया कि धोखाधड़ी के बाद सिम कार्ड नष्ट कर दिए गए थे। उसने धोखाधड़ी से हासिल रकम लेने के लिए बैंक खातों का इंतजाम किया और पैसे अपने साथी कुंदन को ट्रांसफर कर दिए। सीसीटीवी फुटेज में रवि कुमार को एटीएम से धोखाधड़ी की रकम निकालते हुए भी देखा गया।

आगे की जांच में इटावा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लगभग 23 साल के अरुण सिंह की पहचान हुई। बाद में उसे गाजियाबाद के वैशाली में उसके

किराए के घर से गिरफ्तार किया गया। जांच से पता चला कि अरुण सिंह ने बैंक एजीव्यूटिव बनकर पीड़ित से बात की और लोन दिलाने के झूठे बहाने से संपर्क किया। उसके पास से एक एटीएम कार्ड मिला, जो उस अकाउंट से जुड़ा था जिसमें वेगी की रकम का लगभग 70,000 जमा किया गया था। इसके अलावा, दो मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड भी बरामद किए गए। आरोपी अरुण सिंह से बरामद मोबाइल फोन की जांच के दौरान ग्राहकों की जानकारी और फोन नंबरों की एक लिस्ट मिली। इसकी जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या लोन के लिए आवेदन करने वाले अन्य लोगों को भी निशाना बनाया गया था या निशाना बनाने की योजना थी। आगे की जांच से पता चला कि अरुण सिंह ने यस बैंक के कर्मचारी शिवम ठाकुर की पहचान अपनाई और ग्राहकों से उसी की पहचान का इस्तेमाल करके बात की।

भारत विभाजन विभीषिका को संगीत, रंगमंच और वीडियो के माध्यम से किया गया प्रस्तुत

नई दिल्ली, 14 अगस्त (वेब वार्ता)। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के परिप्रेक्ष्य में डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

पार्टिशन हॉर्सस रिमेंबरेंस डे नाम से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में संगीत, रंगमंच और वीडियो को एक साथ प्रस्तुत करते हुए विभाजन के दौर को दर्शाया गया। कार्यक्रम

आयोजन गुरुवार देर शाम को हुआ। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि संगीत, रंगमंच और वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया यह कार्यक्रम इतिहास की उन मानवीय कहानियों को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने का



प्रयास है, जो विभाजन की त्रासदी के पीछे छुपे दर्द और संघर्ष को सामने लाती हैं।

कपिल मिश्रा ने कहा कि

किया कि 1947 के उस दर्द, बलिदान और उससे मिले सबक को कभी विस्मृत न किया जाए। विभाजन विभीषिका दिवस केवल करोड़ों पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से सीख लेने का संकल्प भी है।

मिश्रा ने कहा कि कोई भी समाज जब अपने इतिहास, बलिदानों और उससे मिले सबक को भूल जाता है, तो उसका भविष्य कमजोर नींव पर खड़ा होता है। विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ हमें यह प्रण दोहराना होगा कि भारत की

एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को कमजोर करने वाली मानसिकता को देश में दोबारा कभी पनपने नहीं देंगे।

कार्यक्रम में सोनम कालरा और उनकी टीम ने ह्यस्टोरीज ऑफ सेपरेशनह्म की विशेष संगीतमय प्रस्तुति दी, जिसमें वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अलगाव, संघर्ष और स्मृतियों से जुड़ी कहानियों को कलात्मक माध्यम से प्रस्तुत किया गया। आयोजन के लिए कपिल मिश्रा ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और कलाकारों का आभार व्यक्त किया।

अदालत ने कूड़ा बीनने वाले नाबालिग से कुकृत्य के दोषी की सजा बरकरार रखी

नई दिल्ली, 14 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11-वर्षीय बेघर बच्चे से कुकृत्य करने के आरोपी की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि सड़कों पर गुजारा करने वाले बच्चे से तारीख, समय या कपड़ों का विवरण उतना सटीकता से देने की उम्मीद नहीं की जा सकती जितनी कि एक व्यवस्थित माहौल में रहने वाले गवाह से की जाती है।

आरोपी की याचिका पर 10 अगस्त को पारित फैसले में न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 (कुकृत्य) और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की धारा-छह (गंभीर रूप से यौन हमला) के तहत उसे दोषी ठहराने संबंधी निचली अदालत के अगस्त 2025 का निर्णय बरकरार रखा। हालांकि, न्यायाधीश ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 20 साल जेल की सजा को घटाकर 10 साल कर दिया। इस बाव में अदालत ने यह आधार दिया कि अपराध के समय इस कुकृत्य के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान था।

पॉक्सो अधिनियम की धारा-छह के तहत न्यूनतम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान 16 अगस्त 2019 से लागू हुआ था। नाबालिग ने आरोप लगाया था कि नवंबर 2016 में जब वह कश्मीरी गेट स्थित रेलवे पुल के नीचे सो रहा था, तब आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। जब नाबालिग ने क्षेत्र में बेघर लोगों को मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने वाले कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की निंदा की, तो उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन पर इसकी सूचना दी थी। आरोपी के वकील ने दावा किया कि उसे फंसाया गया है और दलील दी कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि लड़के की उम्र 12 वर्ष से कम थी। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के समय लड़के ने जो कपड़े पहने थे, उन्हें लेकर उसके बयान में कई विरोधाभास थे। बचाव पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि अपनी सटीक उम्र या जन्म तिथि या अन्य विशिष्ट विवरण बताने में लड़के की असमर्थता का लाभ आरोपी को नहीं मिलेगा।

अदालत ने कहा कि हालांकि अपनी गवाही में पीड़ित ने दावा किया था कि उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी, लेकिन उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उससे सटीक उम्र जानने की उम्मीद करना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि स्कूल के रिकॉर्ड में उसकी जन्म तिथि 12 अक्टूबर 2005 दर्ज है, जिससे तय होता है कि घटना के समय उसकी उम्र 11 वर्ष थी। अदालत ने कहा कि नाबालिग लड़के द्वारा दी गई सभी गवाहियों में आरोपी की पहचान, घटना का स्थान, यौन उत्पीड़न की प्रकृति और घटना के तुरंत बाद के घटनाक्रम का क्रम मूल रूप से एक जैसा रहा।

एनसीआर में पूरे हफ्ते सुहावना रहेगा मौसम

नई दिल्ली, 14 अगस्त (वेब वार्ता)।दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज सुहावना बने रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 14 से 19 अगस्त तक आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और लगभग हर दिन हल्की बारिश के आसार हैं।

राहत की बात यह है कि इस अवधि में किसी भी दिन मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि, बारिश और बादलों के बीच बड़ी हुई नमी के कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 14 अगस्त को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन सामान्य तौर पर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। हवा में नमी का स्तर अधिकतम 85 प्रतिशत और न्यूनतम 70 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है।

15 अगस्त को भी मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहने वाला है। इस दिन अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। आसमान सामान्य तौर पर बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश हो सकती है। हालाँकि, इस दिन उमस ज्यादा परेशान कर सकती है, क्योंकि अधिकतम आर्द्रता 95 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 85 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। 16 अगस्त को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। 17 अगस्त को भी तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आसमान सामान्य तौर पर बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी।

18 अगस्त को अधिकतम तापमान थोड़ा कम होकर 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस दिन भी सामान्य रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार जताए हैं। वहीं, 19 अगस्त को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। इस दिन भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। आर्द्रता अधिकतम 85 प्रतिशत और न्यूनतम 70 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस दिन भी मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। दिल्ली- एनसीआर में बादलों की आवाजाही और रुक-रुककर होने वाली हल्की बारिश से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने से दिन के समय भीषण गर्मी का असर सीमित रहने की उम्मीद है। हालांकि, वातावरण में नमी का स्तर लगातार ऊंचा रहने के कारण बारिश रुकने के बाद उमस और चिपचिपी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है।

एनएसयूआई ने नॉर्थ कैंपस में निकाली तिरंगा यात्रा, छात्रों ने लिया हिस्सा



नई दिल्ली, 14 अगस्त (वेब वार्ता)। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नॉर्थ कैंपस में राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में तिरंगा मार्च आयोजित किया। इस मार्च में एनएसयूआई के हजारों सदस्यों और छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तिरंगा यात्रा एसओएल गेट से शुरू होकर रामजस चौक पर समाप्त हुआ। छात्रों ने हाथों में तिरंगा लेकर स्वतंत्रता, एकता, लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों के समर्थन में नारे लगाए। इस अवसर पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा एवं उन्हें मजबूत करना विश्वविद्यालयों की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय लोकतांत्रिक समाज की नींव हैं। छात्रों को बिना किसी डर के अपनी बात रखने, अपनी आवाज उठाने, सवाल पूछने और विचार-विमर्श में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विनोद जाखड़ ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा प्राप्त करने के केंद्र नहीं हैं, बल्कि ऐसे संस्थान भी हैं जहां युवा लोकतंत्र, संवैधानिक अधिकार, समानता और असहमति के सम्मान जैसे मूल्यों को सीखते हैं।

अदालत ने कूड़ा बीनने वाले नाबालिग से कुकृत्य के दोषी की सजा बरकरार रखी

नई दिल्ली, 14 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11-वर्षीय बेघर बच्चे से कुकृत्य करने के आरोपी की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि सड़कों पर गुजारा करने वाले बच्चे से तारीख, समय या कपड़ों का विवरण उतना सटीकता से देने की उम्मीद नहीं की जा सकती जितनी कि एक व्यवस्थित माहौल में रहने वाले गवाह से की जाती है।

आरोपी की याचिका पर 10 अगस्त को पारित फैसले में न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 (कुकृत्य) और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की धारा-छह (गंभीर रूप से यौन हमला) के तहत उसे दोषी ठहराने संबंधी निचली अदालत के अगस्त 2025 का निर्णय बरकरार रखा। हालांकि, न्यायाधीश ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 20 साल जेल की सजा को घटाकर 10 साल कर दिया। इस बाव में अदालत ने यह आधार दिया कि अपराध के समय इस कुकृत्य के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान था।

पॉक्सो अधिनियम की धारा-छह के तहत न्यूनतम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान 16 अगस्त 2019 से लागू हुआ था। नाबालिग ने आरोप लगाया था कि नवंबर 2016 में जब वह कश्मीरी गेट स्थित रेलवे पुल के नीचे सो रहा था, तब आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। जब नाबालिग

उप मुख्यमंत्री डॉ. शुक्ल ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीज श्री विनोद कुमार के स्वास्थ्य की जानकारी ली



इन्दौर, निप्र। उप मुख्यमंत्री डॉ. राजेन्द्र शुक्ल बुधवार को इंदौर प्रवास पर आये। यहां उन्होंने मेदांता अस्पताल पहुंचकर उपचार के लिये भर्ती श्री विनोद कुमार के स्वास्थ्य की जानकारी ली, चिकित्सकों को निर्देश दिये कि उपचार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाये। बेहतर से बेहतर इलाज अस्पताल के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव मुसाद हासानी और संबंधित चिकित्सक उपस्थित थे।

हरियाली अमावस्या पर धन्वंतरि आयुर्वेद महाविद्यालय में हुआ त्रिवेणी रोपण कार्यक्रम



उज्जैन, निप्र। शासकीय धन्वंतरि आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में हरियाली अमावस्या के अवसर पर बुधवार को पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से त्रिवेणी का रोपण किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ओ.पी. व्यास सहित डॉ. नृपेन्द्र मिश्रा, डॉ. दिवाकर पटेल, डॉ. शिरोमणि मिश्रा, डॉ. शिवकुमार मिश्रा, डॉ. योगेश वाणे, डॉ. निरंजन सराफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम महाविद्यालय परिसर स्थित औषधी विद्यावन में त्रिवेणी नीम, बरगद, पीपल के पौधों का रोपण कर उनके संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों एवं प्रकृति का विशेष महत्व है। प्राचार्य डॉ. व्यास ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करना और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करना आवश्यक है। उन्होंने सभी से पौधारोपण को सामाजिक दायित्व के रूप में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन पौधों की देखभाल एवं पर्यावरण संरक्षण के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ। इस अवसर पर शिक्षक अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

मानसून जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए फील्डस्तर तक निगरानी रखे-संभागायुक्त श्री सिंह

उज्जैन, निप्र। संभागायुक्त श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उज्जैन संभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभाग के समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन उपस्थित रहे। बैठक में मातृ एवं बाल मृत्यु समीक्षा, गैर-संचारी रोगों का नियंत्रण, टीबी रोगियों को पोषण सहायता, सिकल सेल जांच एवं उपचार, मानसून जनित बीमारियों की रोकथाम तथा चिकित्सालय प्रबंधन सहित प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। संभागायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मातृ - मृत्यु के प्रकरणों , सीबीएमडीएसआर , बाल मृत्यु (सीडीआर) के प्रतिशत में सुधार लाये ताकि रिपोर्टिंग एवं समीक्षा की प्रक्रिया और प्रभावी बने। मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप के मरीजों की नियमित स्क्रीनिंग, फॉलोअप तथा उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (निश्चय मित्र योजना) के अंतर्गत टीबी रोगियों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने हेतु 6 अतिनवार्य उच्च-प्रोटीन खाद्य सामग्रियों वाली फूड बास्केट/पोषण किट वितरण की समीक्षा की गई। समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि अधिसूचित मरीजों को निर्धारित किट समय पर उपलब्ध करवायें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशा के अनुरूप राजस्व सेवाओं को बनाया जा रहा त्वरित और सुगम

किसानों को तत्काल मिले आदेश एवं प्रमाणित दस्तावेज

इन्दौर , निप्र। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप आमजन को शासकीय सेवाओं का लाभ सरल, सहज एवं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में इंदौर जिला प्रशासन द्वारा निरंतर नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की पहल पर नागरिकों के राजस्व संबंधी कार्यों के त्वरित निराकरण एवं राजस्व अभिलेखों के अद्यतन के लिए राजस्व निरीक्षक वृत्तों में राजस्व शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज बुधवार को तीन स्थानों रंगवासा, लसुडिया परमार और ?पिपल्याराव में विशेष राजस्व शिविर आयोजित किये गये। इन शिविरों में कुल 220 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी नवाचार के तहत बुधवार, 12 अगस्त को तहसील देपालपुर के ग्राम रंगवासा में राजस्व शिविर आयोजित किया गया। शिविर में आमजन एवं कृषकों को राजस्व संबंधी सेवाएं मौके पर ही उपलब्ध कराते हुए कुल 77 प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया।

शिविर में 47 नामांतरण, 4 बंटवारा एवं 5 नक्शा तरमीम प्रकरणों में तत्काल आदेश पारित किए गए। इन आदेशों का राजस्व अभिलेखों में तत्काल अमल करते हुए संबंधित कृषकों को आदेश एवं खसरे की प्रमाणित प्रतियां भी मौके पर उपलब्ध कराई गईं। इसके अलावा 21 सीमांकन प्रकरणों का भी सफलतापूर्वक निराकरण किया गया।

इस पहल से किसानों एवं आम नागरिकों को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक ही स्थान पर प्रकरणों की सुनवाई, आदेश पारित करने, अभिलेखों में अमल तथा प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराने की कार्रवाई से नागरिकों को त्वरित राहत मिली। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के इस नवाचार का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को सरल, सुलभ, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना तथा राजस्व अभिलेखों को अद्यतन रखना है। शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ही



लसुडिया परमार में आयोजित हुआ राजस्व शिविर

सांवेर तहसील के टप्पा क्षिप्रा के गांव लसुडिया परमार में विशेष राजस्व जनकल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन एवं हितग्राही शामिल हुए। शिविर में नामांतरण के कुल 80 प्रकरण,बंटवारा के 05 प्रकरण,सीमांकन के 4,नक्शा तरमीम के 6,रास्ता विवाद के 3 प्रकरण सहित कुल 100 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। ई-केवायसी, सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ताओं को बुलवा कर उनकी समस्याओं का निदान भी हाथों-हाथ किया गया। कृषकों को आदेश की प्रतियां एवं संशोधित खसरा उपलब्ध करवाए गए। गांव में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। ग्रामीणों द्वारा अन्य विभागों से संबंधित आवेदनों को लिया जाकर संबंधित विभाग को भेजा गया।

हर घर तिरंगा अभियान के तहत नौगावां में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए कलेक्टर

झाबुआ, निप्र। हर घर तिरंगा अभियान के तहत एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौगावां में राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट सम्मिलित हुए। बारिश के बावजूद विद्यार्थियों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों में अभियान को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न वीर सेनानियों एवं महापुरुषों की वेशभूषा धारण कर उनके योदान को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर बलिदानियों के त्याग, संघर्ष और राष्ट्रसेवा का स्मरण किया गया। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने विद्यार्थियों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि बारिश भी बच्चों के हसलों और राष्ट्रभक्ति के जज्बे को कम नहीं कर पाई है। स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों एवं महापुरुषों की वेशभूषा में विद्यार्थियों को देखकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि



जिन वीरों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, उनके जीवन और योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का यह सराहनीय प्रयास है। कलेक्टर ने कहा कि नौगावां विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा जिस उत्साह एवं समर्पण के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य विद्यार्थियों के हाथों में है और उनमें दिखाई दे रही राष्ट्रप्रेम की भावना यह विश्वास दिलाती है कि देश का भविष्य मजबूत

हाथों में सुरक्षित है। कलेक्टर डॉ. भरसट ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का जीवन और योगदान से नई पीढ़ी को छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति, उसके मन में भारतीय होने का गर्व और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को और अधिक मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अभियान को राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की भावना से भी जोड़ा गया है। राष्ट्रीय गीत की छह पंक्तियों के माध्यम से इसके गौरव और संदेश को घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास

एड्स जागरूकता हेतु उज्जैन में निकाली गई बाइक रैली

उज्जैन, निप्र। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में 12 अगस्त से 12 अक्टूबर 2026 तक सघन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य आमजन को एचआईवी/एड्स संक्रमण के कारणों, बचाव के उपायों, जांच एवं उपचार तथा एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के प्रति अपनाए जाने वाले सकारात्मक व्यवहार के संबंध में जागरूक करना है।इस संबंध में क्षेत्रीय संचालक डॉ. दीपक पिप्पल द्वारा संबंधित विभागों एवं संस्थाओं को अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार पटेल ने बताया कि अभियान के दौरान उज्जैन जिले में 167 ग्रामों में ग्राम स्तरीय बैठकें, 25 ग्रामों में ग्राम सभाएं, 25 आंगनवाड़ी केंद्र, 20 महिला विद्यालय तथा 135 विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।बाइक रैली का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार पटेल द्वारा हरी



झंडी दिखाकर किया गया। रैली विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुनीता परमार, जिला नोडल अधिकारी एड्स कार्यक्रम डॉ. अरुण कुशवाहा, दिशा टीम से शोभी गुप्ता सहित विभाग के विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।नोडल अधिकारी डॉ. अरुण कुशवाहा ने कहा कि एचआईवी/एड्स के संबंध में सही जानकारी ही इसके संक्रमण की रोकथाम का सबसे प्रभावी माध्यम है।

एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे आवश्यक जांच, परामर्श एवं उपचार सेवाओं से जोड़कर सामान्य एवं सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

धार, निप्र। मध्यप्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा मुख्यालय होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, भोपाल के निर्देशानुसार धार में 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक 7 दिवसीय सिविल डिफेंस क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम-2026 आयोजित किया गया। जिसका समापन बुधवार को हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 150 सिविल डिफेंस वालंटियर्स ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रशिक्षण का उद्देश्य स्वयंसेवकों को आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित, सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं व्यवहारिक दक्षता प्रदान करना था। इस सात दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान स्वयंसेवकों को विभिन्न भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे आवश्यक जांच, परामर्श एवं उपचार सेवाओं से जोड़कर सामान्य एवं सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

किया जा रहा है। पूर्व विधायक श्री कलसिंह भाबर ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। तिरगे की शान प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करती है।

उन्होंने सभी नागरिकों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने तथा परिवार के साथ हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक सहभागिता करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के उपरांत तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। बारिश के बीच भी प्रतिभागियों का उत्साह बना रहा और पूरा वातावरण तिरंगामय एवं देशभक्ति से ओत-प्रोत नजर आया। साथ ही अतिथियों द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधिगण, सहायक कलेक्टर सुश्री आयुषी बंसल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर सुश्री अवनधती प्रधान, अन्य अधिकारी कर्मचारी, शिक्षक एवं छात्र- छात्राएं उपस्थित रहे।

धार में 7 दिवसीय सिविल डिफेंस क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम-2026 का सफल समापन हुआ



खोज एवं बचाव कार्य, प्राथमिक उपचार, सीपीआर, अग्नि सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरणों का उपयोग, आपातकालीन संचार, राहत एवं बचाव कार्य, आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया, सामुदायिक जागरूकता तथा संकट की परिस्थितियों में स्वयंसेवकों की भूमिका आदि पर विशेष बल दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान स्वयंसेवकों को विभिन्न व्यावहारिक अभ्यास एवं डेमो के माध्यम से आपातकालीन

परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित एवं समन्वित ढंग से राहत एवं बचाव कार्य करने की तकनीकों की जानकारी दी गई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डिवीजनल कमाण्डेंट होमगार्ड संभाग इंदौर श्रीमती प्रीतिबाला सिंह

का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का जीवन और योगदान से नई पीढ़ी को छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति, उसके मन में भारतीय होने का गर्व और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को और अधिक मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अभियान को राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की भावना से भी जोड़ा गया है। राष्ट्रीय गीत की छह पंक्तियों के माध्यम से इसके गौरव और संदेश को घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास



रोड के निर्माण कार्य की भी जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को कार्य में तेजी लाते हुए आगामी एक सप्ताह के भीतर सीसी रोड का निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य के दौरान यातायात व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा वैकल्पिक मार्ग की नियमित निगरानी करते हुए आवश्यकता के अनुसार तत्काल सुधार कार्य सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान सहायक कलेक्टर सुश्री आयुषी बंसल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर सुश्री अवनधती प्रधान एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

की विशेष उपस्थिति रही। जिनके द्वारा वालंटियर्स को जैकेट वितरित की गई साथ ही उनके द्वारा प्रशिक्षण के दौरान स्वयंसेवकों द्वारा किए गए प्रयासों एवं सहभागिता की सराहना की गई। इस अवसर पर उनके द्वारा स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा गया कि आपदा के समय प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले प्रशिक्षित स्वयंसेवक प्रशासन और आमजन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्रत्येक स्वयंसेवक का प्रशिक्षित, अनुशासित, संवेदनशील एवं सेवा-भाव से परिपूर्ण होना आवश्यक है। साथ ही यह भी बताया गया कि सिविल डिफेंस की प्रभावशीलता केवल आपदा के समय किए जाने वाले राहत एवं बचाव कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा से पूर्व तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण, जन-जागरूकता एवं सामुदायिक क्षमता निर्माण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

परिस्थितियों में टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता तथा उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग का अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षकों द्वारा वास्तविक आपदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित एवं समन्वित ढंग से राहत एवं बचाव कार्य करने की तकनीकों की जानकारी दी गई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डिवीजनल कमाण्डेंट होमगार्ड संभाग इंदौर श्रीमती प्रीतिबाला सिंह

का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का जीवन और योगदान से नई पीढ़ी को छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति, उसके मन में भारतीय होने का गर्व और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को और अधिक मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अभियान को राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की भावना से भी जोड़ा गया है। राष्ट्रीय गीत की छह पंक्तियों के माध्यम से इसके गौरव और संदेश को घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास

नारायण डेयरी से 350 किलो पनीर जप्त
एक अन्य कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा नारायण डेयरी, ग्राम अकनवी, तहसील महु, इंदौर का निरीक्षण किया गया। मौके से खाद्य पदार्थ पनीर के 3 नमूने जांच हेतु लिए गए। पनीर की गुणवत्ता एवं उसके डेयरी एनालॉग होने की संभावना के दृष्टिगत लगभग 350 किलोग्राम पनीर, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹1,05,000 है, को जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक जप्त किया गया। लिए गए नमूने परीक्षण हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं।

मोहनी मावा भंडार से 716 किलो डेयरी एनालॉग मावा जप्त

इसी क्रम में नंदा नगर स्थित मोहनी मावा भंडार का निरीक्षण किया गया।

डेयरी एनालॉग पर प्रतिबंध के आदेश के परिपालन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

1816 किलो डेयरी एनालॉग खाद्य पदार्थ जप्त, अनुमानित कीमत ₹4.72 लाख, पनीर निर्माण इकाई का कार्य तत्काल प्रभाव से बंद

इन्दौर , निप्र। मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनस्वास्थ्य एवं उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए डेयरी एनालॉग एवं वास्तविक दुग्ध उत्पादों का आभास कराने वाले गैर-दुग्ध खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय, आपूर्ति एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के अनुसार ऐसे उत्पादों के संबंध में उपभोक्ताओं को भ्रमित होने से बचाने, उत्पाद की वास्तविक प्रकृति एवं पहचान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेश के परिपालन में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर इंदौर श्री शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला इंदौर



द्वारा आज दिनांक 12 अगस्त 2026 को विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर डेयरी एनालॉग एवं वास्तविक दुग्ध उत्पादों के रूप में विक्रय किए जा रहे खाद्य पदार्थों की जांच हेतु नमूना कार्रवाई की गई तथा सदिग्ध/प्रतिबंधित श्रेणी के खाद्य

पदार्थों के स्टॉक को जप्त किया गया।

उमापति इंडस्ट्रीज में लो-फैट पनीर की जांच, 450 किलो पनीर जप्त; निर्माण कार्य तत्काल बंद
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा उमापति इंडस्ट्रीज,

305/2 पार्ट-10, पालदा, इंदौर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रोपराइटर श्री सावन उपाध्याय उपस्थित पाए गए। परिसर में लो-फैट पनीर का निर्माण एवं पैकिंग किया जाना पाया गया। परिसर के निरीक्षण के दौरान ड्रेनेज व्यवस्था उचित नहीं पाई गई तथा परिसर की दीवारें गंदी पाई गईं। रॉ मटेरियल पैलेट्स पर व्यवस्थित रूप से रखा हुआ नहीं पाया गया तथा भंडारण व्यवस्था भी अव्यवस्थित पाई गई। खाद्य पदार्थ के लेबल पर अंकित न्यूट्रीशनल इन्फॉर्मेशन के संबंध में आवश्यक जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं पाई गई। इसके अतिरिक्त इंग्रीडिएंट लिस्ट के अनुसार पनीर के निर्माण में पानी का उपयोग किया जाना पाया गया, किंतु उपयोग किए जा रहे पानी की जांच संबंधी रिपोर्ट भी मौके पर उपलब्ध नहीं पाई गई। परिसर में निर्मित एवं पैक किए जा रहे लो-फैट पनीर का नमूना जांच हेतु लिया गया। साथ ही खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता एवं निर्माण परिस्थितियों के संबंध में सदिग्धता के आधार पर लगभग 450 किलोग्राम पनीर, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹1,17,000 है, को विलेप्शन रिपोर्ट प्राप्त होने तक जप्त किया

इंदौर में वीआईपी नंबर प्लेट का क्रेज

आरटीओ ने इन्हें बेचकर कमा लिए 20 करोड़ रुपये

इंदौर। इंदौर शहर में सड़कों पर लगातार बढ़ती वाहनों की संख्या के साथ गाड़ियों पर वीआईपी नंबर लगवाने का क्रेज भी तेजी से बढ़ रहा है। आरटीओ इस साल पहले सात महीने में वीआईपी नंबर बेचकर 20 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

इंदौर में गाड़ियों पर वीआईपी नंबर लगाना स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। वहीं कुछ लोग अपने लकी नंबर को खरीदते हैं। एक जनवरी से 31 जुलाई तक इंदौर आरटीओ ऑफिस से 11,746 वीआईपी नंबर खरीदे गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इनमें से 20 सबसे ज्यादा डिमांड वाले नंबरों से इंदौर आरटीओ को 75 लाख रुपये और इसके अलावा 58 चुने हुए नंबरों से 82 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई हुई है। इंदौर में वीआईपी फैंसी नंबर प्लेट का क्रेज नया नहीं है, 2015 में एम्पी 09 सीएस 001 नंबर 9.62 लाख रुपये में बिका था। हर साल आरटीओ को

वीआईपी नंबरों से करोड़ों की कमाई हो रही है। पिछले साल 2025 में 11.40 करोड़ रुपये और 2024 में 11.01 करोड़ रुपये के वीआईपी नंबर इंदौर आरटीओ द्वारा बेचे गए। इंदौर आरटीओ में सबसे ज्यादा डिमांड 1 से 9 तक सिंगल डिजिट वाले नंबरों की रहती है। इसके साथ ही 111, 222, 77, 88 नंबरों के साथ 0786 और 0909 सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं। इनमें ज्यादातर नंबर ऐसे हैं जिन्हें पाने के लिए कई लोग आवेदन करते हैं। ऐसे नंबरों को ऑनलाइन बिडिंग के जरिए दिया जाता है।

गाड़ी की कैटेगरी और नंबर की सीरीज के अनुसार वीआईपी और फैंसी नंबरों की कीमत 2 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक होती है। ऑनलाइन सिस्टम में टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों वाहनों के लिए बिडिंग की जाती है। इस साल सबसे ऊंची बोली एम्पी 09 एवी 0001 नंबर के लिए 5.55 लाख रुपये रही थी।

नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी के ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस का छापा आय से 216 प्रतिशत ज्यादा मिली संपत्ति

इंदौर। नगर निगम इंदौर के सहायक राजस्व अधिकारी जितेंद्र कुमार पांडेय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार सुबह अधिकारी के इंदौर स्थित दो ठिकानों पर एक साथ सर्च शुरू की।

लोकायुक्त के मुताबिक, जितेंद्र कुमार के करीब 31 वर्ष के सेवाकाल में अनुमानित वैध आय करीब 80 लाख रुपये आंकी गई है,



जबकि उनकी ओर से करीब 2.53 करोड़ रुपये की संपत्ति और अन्य

मध्य प्रदेश में रोजाना गायब हो रहे 130 बच्चे और महिलाएं जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान, हाई कोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

इंदौर। पदेश में रोजाना 130 से ज्यादा बच्चियां और महिलाएं लापता हो रहे हैं। स्थिति पूरे प्रदेश में एक जैसी है। लापता हो चुके लोगों की संख्या हजारों में हैं। बावजूद इसके शासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। जिन पर कार्रवाई की जिम्मेदारी है वे इस पर ध्यान नहीं दे रहे।

आंकड़े सार्वजनिक करने के बजाय इसे छुपाया जा रहा है। गुरुवार को इस संबंध में प्रस्तुत जनहित याचिका में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य और केंद्र शासन सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

हाई कोर्ट में यह जनहित

याचिका अभिजीत पांडेय ने एडवोकेट शुभम मांडिल के माध्यम से दायर की है। कहा है कि इंदौर सहित पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे लापता हो रहे हैं, लेकिन उनकी तलाश, जांच और निगरानी के लिए प्रभावी व्यवस्था नहीं है। प्रदेश में प्रतिदिन 130 महिलाएं और बच्चे लापता हो रहे हैं। याचिका में यह भी कहा है कि याचिका किसी व्यक्तिगत विवाद को लेकर नहीं बल्कि महिलाओं और बच्चों के जीवन, सुरक्षा और गरिमा के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत की गई है। लापता महिलाओं और बच्चों के मामले मानव तस्करी, शोषण, यौन अपराध और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े हो सकते हैं, इसलिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।

आंकड़ों के माध्यम से बताई भयावहता



याचिका में आंकड़ों के माध्यम से स्थिति की भयावहता बताई गई है। कहा है कि वर्ष 2023 से पहले तक प्रदेश में लापता होने वाली महिलाओं की संख्या 35000 थी, लेकिन वर्ष 2023 में यह आंकड़ा 74 हजार पर पहुंच गया। इसी तरह वर्ष 2023 तक प्रदेश में गायब होने वाली बच्चियों की संख्या 3926 थी जो वर्ष 2023 में 16 हजार 17 पर पहुंच गया।

आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023

में लापता होने वाली महिलाओं की संख्या के हिसाब से मप्र देश में पहले स्थान पर था जबकि बच्चियों के गायब होने के मामले में देश में चौथे स्थान पर। याचिका में सरकारी जवाब का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि वर्ष 2020 से 28 जनवरी 2026 तक पूरे प्रदेश से 2,74,311 महिलाएं और लड़कियां लापता हुईं। इसका मतलब है कि राज्य में प्रतिदिन 130 महिलाएं और बच्चियां

शिल्पियों की कला को सम्मान, हुनर को मिला हौसला

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार के तहत उत्कृष्ट शिल्प के लिए चयनित शिल्पियों को सम्मानित किया है। विगत दिनों शिल्पियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ये सम्मान उन शिल्पकारों के हुनर को प्रोत्साहित करने का माध्यम हैं, जो अपनी कला के जरिए मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक शिल्प केवल उत्पाद नहीं हैं, बल्कि पीढ़ियों से हस्तांतरित ज्ञान, कौशल और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक हैं।

में करीब 14 लाख रुपये खर्च होना बताया गया है।

लोकायुक्त टीम ने किया मामला दर्ज

लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 13(1) (बी) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है। डीएसपी सुनील तालान और आनंद चौहान सहित निरीक्षक आशुतोष मिठास व सचिन पटेरिया की टीम सर्चिंग कर रही है। कार्रवाई अभी जारी है।

इंदौर-खंडवा रेल लाइन : ऑंकरेश्ववर रोड रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का काम पूरा, जल्द शुरू होगी ट्रेनों की आवाजाही

इंदौर। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में इंदौर-खंडवा गेज कन्वर्जन परियोजना के तहत ऑंकरेश्वर रोड रेलवे स्टेशन पर सिग्नलिंग संबंधी महत्वपूर्ण कार्य गुरुवार को पूरा कर लिया। सिग्नलिंग विभाग द्वारा स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का कार्य पूरा कर सफलतापूर्वक कमीशनिंग (चालू करना) किया। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार ट्रेन परिचालन में संरक्षा की दृष्टि से सिग्नलिंग सिस्टम काफी महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे कमिशन किया जा चुका है। ऑंकरेश्वर रोड स्टेशन पर रेलवे ट्रैक से संबंधित



महत्वपूर्ण सीआरएस निरीक्षण पूर्व में ही पूरा किया जा चुका है। अब

सिग्नलिंग कार्य के पूर्ण होने से स्टेशन को यात्री परिचालन के लिए तैयार

करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है।

स्टेशन भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है

ऑंकरेश्वर रोड रेलवे स्टेशन के स्टेशन भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। प्लेटफॉर्म व यात्रियों से संबंधित आवश्यक सुविधाओं के कार्य भी पूरे किए जा चुके हैं। निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद इस खंड को यात्री ट्रेन परिचालन के लिए खोलने की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अपर मंडल रेल प्रबंधक कुंजीलाल मीणा ने निर्माण, सिग्नलिंग, विद्युतीकरण, पावर सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ ऑंकरेश्वर

रोड स्टेशन का निरीक्षण किया।

स्टेशन पर तेजी से चल रहे हैं विभिन्न कार्य, जल्द होंगे पूरे

स्टेशन पर चल रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इंदौर-खंडवा गेज कन्वर्जन परियोजना के तहत ऑंकरेश्वर रोड स्टेशन पर सिग्नलिंग, विद्युतीकरण, स्टेशन भवन, प्लेटफार्म एवं यात्री सुविधाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति से इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना को यात्री परिचालन के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

मिनी ट्रक में भरकर ग्वालियर हाई कोर्ट पहुंची सड़कों की 5 साल के रिकार्ड की हजारों फाइलें 8 मुख्य सड़कों की होगी सैंपलिंग जांच

ग्वालियर। शहर की सड़कों के निर्माण और मरम्मत में गुणवत्ता को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई हुई। नगर निगम की ओर से वर्ष 2021 से अब तक सड़कों पर हुए काम का रिकार्ड मिनी ट्रक और एक टेंपो में भरकर कोर्ट पहुंचाया गया। इसमें हजारों फाइलें थीं। न्यायालय ने रिकार्ड की सूची अपने पास जमा करा ली, जबकि फाइलों को वापस कर दिया। सुनवाई के दौरान रिकार्ड की सूची से एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। नगर निगम ने तीनों शहरी विधानसभा क्षेत्रों में कराए गए सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। बताया गया कि इसमें कई मुख्य मार्ग का रिकार्ड शामिल नहीं था। सूची में मुख्य रूप से गली-मोहल्लों और छोटी सड़कों पर हुए कार्यों का विवरण दिया गया था। अब इस मामले में आठ सड़कों के सैंपल लिए जाएंगे जिसमें एक एनएचएआइ, एक पीडब्ल्यूडी और छह सड़कें नगर निगम की हैं। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

चिह्नित सड़कों के लिए जांचगे सैंपल
सुनवाई के दौरान आठ सड़कों को गुणवत्ता परीक्षण के लिए चिह्नित किया गया है। इनहीं सड़कों का रिकार्ड कोर्ट में पेश किया जाएगा साथ ही सैंपल की जांच कर कोर्ट कमिश्नर द्वारा रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की जाएगी। निरीक्षण के दौरान एएसपी धर्मवीर सिंह स्वयं मौजूद रहेंगे और सैंपल की कार्रवाई के दौरान यातायात बाधित न हो इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। सैंपलिंग के दौरान सड़क की मोटाई और निर्माण में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जाएगी।

आठ सड़कों के बाढ़ बांधी पट वाट होगी
न्यायालय ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि पहले आठ सड़कों को चुनकर उनके सैंपल कराए जाएंगे और उनकी गुणवत्ता को जांचा जाएगा। इसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सुनवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं इन आठ सड़कों के निरीक्षण और सैंपलिंग के बाद ही कोर्ट शहर की अन्य सड़कों की ओर रुख करेगा। इस मामले में न्यायालय ने अधिवक्ता गौरव समाधिया, उपन रघुवंशी और हिमांशु शर्मा को कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया है। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया है कि निरीक्षण के दौरान यह मौके पर मौजूद रहेंगे और सैंपलिंग की प्रक्रिया पूरी करवाएंगे। इसके साथ ही न्यायालय ने रिपोर्ट को भी कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से ही पेश किया जाएगा। (बात दें कि इस मामले में निरीक्षण और सैंपलिंग कब होना है इसे न्यायालय की अगली सुनवाई में सोमवार को तय किया जाएगा।।

पेंच टाइगर रिजर्व में डायनामाइट से मछली का शिकार: बाघों की सुरक्षा पर संकट

भोपाल। पेंच टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र स्थित तोतलादोह जलाशय में कथित अवैध मछली शिकार और संगठित कारोबार की शिकायत को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंची शिकायत के बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथॉरिटी (एनटीसीए) ने मध्य प्रदेश सरकार से इस मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है।

एनटीसीए ने प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन को शिकायत की गंभीरता से जांच कर अवैध गतिविधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद पेंच नदी और तोतलादोह जलाशय के कोर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मछली का अवैध शिकार किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इसे संगठित सिंडिकेट बताते हुए आरोप लगाया है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं और मछलियों को



मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा व सिवनी के रास्ते महाराष्ट्र के बाजारों तक भेजा जाता है।
डायनामाइट से मछली शिकार का आरोप
छिंदवाड़ा निवासी कैप्टन ब्रजेश भारद्वाज की ओर से पीएमओ को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मछली पकड़ने के लिए जलाशय में डायनामाइट जैसे विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता है।

शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि अवैध शिकार रोकने पहुंचने वाले वन विभाग के गश्ती दल और विशेष बल सुरक्षा बल के सदस्यों पर फायर बम और बंदूकों

से हमले किए जाते हैं।

शिकायत में हाल में वनकर्मियों की नावों को आग लगाए जाने की घटना का भी उल्लेख किया गया है। इस पूरे मामले में एनटीसीए ने प्रदेश से पूर्व में की गई कार्रवाई और वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी है।

सैकड़ों करोड़ के कारोबार का दावा

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि तोतलादोह में अवैध मछली कारोबार अब संगठित सिंडिकेट का रूप ले चुका है और इसका वार्षिक कारोबार सैकड़ों करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। आरोप के मुताबिक, बफर क्षेत्र के आसपास के कुछ

गांवों से बड़ी संख्या में लोग शाम के समय कोर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और रातभर मछली पकड़ने के बाद सुबह के समय इसे बाहर निकालते हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि मछलियों को छिंदवाड़ा और सिवनी के रास्ते महाराष्ट्र के नागपुर, सावनेर और खापा के बाजारों में भेजा जाता है। इसके लिए पिकअप, बोलेरो, वैन और अन्य वाहनों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

145 मछुआरा परिवारों के पुनर्वास का भी उल्लेख

शिकायत में सरकारी रिकॉर्ड का

हवाला देते हुए कहा गया है कि पेंच नेशनल पार्क के गठन से पहले क्षेत्र में मछुआरा परिवारों के अधिकारों का निपटारा किया गया था। वर्ष 2001-02 में छिंदवाड़ा कलेक्टर के माध्यम से 145 पात्र मछुआरा परिवारों का विस्थापन और पुनर्वास किया गया था। इनके पुनर्वास एवं मुआवजे के लिए करीब 72 लाख रुपये वितरित किए जाने का उल्लेख है। कुछ मछुआरों को वन विभाग में रोजगार दिए जाने की बात भी शिकायत में कही गई है।
जलीय जैव-विविधता पर खतरे की आशंका
तोतलादोह जलाशय पेंच के महत्वपूर्ण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। यहाँ मछलियों के अलावा मगरमच्छ, कछुए और विभिन्न प्रजातियों के जलपक्षी पाए जाते हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अवैध गतिविधियों के कारण जलाशय में प्लास्टिक कचरा बढ़ रहा है और नावों की आवाजाही के लिए पानी में मौजूद सूखे पेड़ों को हटाना जा रहा है।
वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, यदि कोर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मानवीय गतिविधियाँ और अवैध शिकार जारी रहता है तो इसका असर जलीय जैव-विविधता के साथ बाघों के प्राकृतिक आवास पर

सूचना के अधिकार में नहीं मिली जानकारी

याचिका में कहा है कि लापता लोगों के बारे में याचिकाकर्ता ने जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से जानकारी चाही थी, लेकिन संतोषजनक जानकारी नहीं मिली। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में मिसिंग पर्सन को लेकर जारी एडवाइज़री को गंभीरता से लिया जाए। इंदौर जिले में लापता महिलाओं और बच्चों के मामलों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जाए। साथ ही राज्य सरकार से वर्ष 2021 से अब तक के मामलों, बरामद हुए लोगों, लॉबित मामलों और उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाए। याचिका में यह मांग भी है कि लापता महिलाओं और बच्चों से संबंधित जिलेवार आंकड़े नियमित रूप से सार्वजनिक किए जाएं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल सेठी उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वे सभी विभागों से जानकारी लेकर कोर्ट के समक्ष रखेंगे। मामले में अब सितंबर में सुनवाई होगी।

विदिशा में छात्राओं के आगे झुका प्रशासन



विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज में निजी बस ऑपरेटरों द्वारा छात्राओं का बस किराया 10 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये करने के फैसले के विरोध में स्कूली छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया। छात्राओं के इस अप्रत्याशित प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में दिख रहा है कि स्कूल खत्म होने के बाद छात्राओं का ग्रुप सिरोंज बस स्टैंड पर जमा हुआ और एक बस के सामने खड़े होकर "विधायक जी, किराया कम करो!" के नारे लगाने लगी। इन छात्राओं में से कई रोजाना आसपास के गांवों से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करके पढ़ाई करने सिरोंज आती हैं।

इस घटना पर कॉंकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का भी रिएक्शन आया है, जिन्होंने हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट-यूजी पेपर लीक के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। दीपके ने वायरल वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, 'एक धर्मद प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा?' मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी को जवाब मिल गया होगा।

आश्वासन मिलने के बाद छात्र हटीं

प्रदर्शन के कारण बस स्टैंड पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ओम नारायण बड़कुल ने छात्राओं से बातचीत कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्राएं वहां से शांत होकर लौटीं।

विधायक उमाकांत शर्मा भी बस स्टैंड पहुंचे

इसी बीच तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे स्थानीय विधायक उमाकांत शर्मा भी बस स्टैंड पहुंचे और अधिकारियों के साथ बस ऑपरेटरों की बैठक ली। बैठक में प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद बस ऑपरेटरों ने किराए की दरों को वापस पुरानी दर यानी 10 रुपये पर तय करने पर सहमति जताई। विधायक शर्मा ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर छात्राओं को बस पास और विशेष किराया छूट देने का भी अनुरोध किया है।

बाघों की सुरक्षा पर संकट भी पड़ सकता है।
कोर क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक
पेंच नेशनल पार्क के कोर क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर केंद्र सरकार पहले भी अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। संसद में उठे एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत नेशनल पार्क के कोर क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है।
केंद्र ने पेंच नेशनल पार्क की सीमाओं में बदलाव अथवा मछली पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के किसी प्रस्ताव से भी इनकार किया था।

अब एनटीसीए की रिपोर्ट पर नजर
एनटीसीए की ओर से एटीआर मागे जाने के बाद अब मध्य प्रदेश वन विभाग को शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच और अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा देना होगा। रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि तोतलादोह जलाशय के कोर क्षेत्र में अवैध मछली शिकार की शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और आज इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज विनय कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी



गुवाहाटी। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज विनय कुमार को आगामी 2026/27 घरेलू सत्र के लिए कर्नाटक की सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। 42 वर्षीय विनय कुमार येर गौड़ की जगह लेंगे। गौड़ अब बंगलूरू स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (सीओई) में बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज दीपक चौगुले की टीम का फिलिंडंग कोच नियुक्त किया गया है।

पहली बार बने सीनियर टीम के मुख्य कोच
यह पहली बार है जब विनय कुमार कर्नाटक की सीनियर टीम के मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे। इससे पहले वह महाराजा टी20 ट्रॉफी में हुबली टाइगर्स के मुख्य कोच रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने आईएलटी20 में एमआई एमिरेट्स के गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी भी संभाली है। विनय ने 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के बाद आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के टैलेंट स्काउट के तौर पर भी काम किया। वह स्टार स्पोर्ट्स कन्ट्रिड के कमेंटेटर भी रहे हैं।

स्पेन के हर्नांडेज बने नीदरलैंड फुटबॉल टीम के नये कोच

साल 2030 फीफा विश्व कप तक टीम के साथ रहेंगे

एम्स्टर्डम। नीदरलैंड फुटबॉल संघ ने रोनाल्ड कोमैन की जगह स्पेन के पूर्व फुटबॉलर जावी हर्नांडेज को अपनी फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच बनाया है। हर्नांडेज डच टीम के कोच बनाये गये पहले विदेशी है।

इसलिए यह नियुक्ति बेहद अहम मानी जा रही है। वह साल 2030 अनुबंध फीफा विश्व कप तक डच टीम के कोच बने रहेंगे। कोच बनाये जाने से उत्साहित हर्नांडेज ने खुशी जताते हुए कहा, , नीदरलैंड की नेशनल टीम का मुख्य कोच बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। उन्होंने अपने करियर के दौरान डच



फुटबॉल के साथ अपने गहरे संबंध के बारे में भी बताया। नये कोच ने कहाकि एफसी बार्सिलोना एकेडमी में रहने और जोहान क्रूफ तथा रिनस मिशेल्स जैसे डच दिग्गजों से मिली सीख के कारण, वह डच फुटबॉल से एक विशेष संबंध महसूस करते हैं। उन्होंने यहां तक

कहा, आप कह सकते हैं कि मैं एक तरह से डच फुटबॉल का ही एक बेटा हूं। उन्होंने लुइस वैन गाल, जिनके नेतृत्व में उन्होंने बार्सिलोना में अपना डेब्यू किया, और फ्रैंक रिजकार्ड जैसे अन्य महान कोचों को भी याद किया, जिन्होंने उन्हें एक खिलाड़ी और एक कोच, दोनों के

स्वितातेक ने रायबकिना को हराकर नेशनल बैंक ओपन खिताब जीता



करते हुए बढ़त बना ली। इस ब्रेक के बाद उन्होंने अपनी लय बनाए रखी और 6-3 से दूसरा सेट जीतकर मैच अपने नाम कर लिया।

इस खिताब को जीतने के साथ ही स्वितातेक अब ताजा डब्ल्यूटीए (डब्ल्यूटीए) रैंकिंग में दो स्थान की छलांग लगाकर पांचवे नंबर पर पहुंच

जाएंगी। वहीं फाइनल में हार के बाद भी रायबकिना रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बरकरार रहेंगी। इस जीत से स्वितातेक का मनोबल भी बढ़ेगा। दूसरी ओर

महिलाओं के युगल फाइनल में चेक गणराज्य की अनुभवी खिलाड़ी कतेरीना सिनीयाकोवा और चीन की शुआई झांग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताबी

रियल मैड्रिड से खेलेंगे कार्लोस
मैड्रिड। स्पेन के शीर्ष फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने लेवांते के युवा स्ट्राइकर कार्लोस एस्पी को अपने साथ जोड़ा है। रियल मैड्रिड ने एस्पी को करीब 25 मिलियन यूरो की मोटी रकम देकर खरीदा है। ऐसे में अब अगल सत्र से कार्लोस रियल की ओर से खेलते हुए दिखेंगे। रियल ने कहा कि कार्लोस अगले पांच साल तक उसके पास ही रहेंगे। इसके तहत ये फुटबॉलर जून, 2031 तक रियल की ओर से खेलेंगे। गौरतलब है कि रियल मैड्रिड में आने से पहले कार्लोस ने लेवांते की ओर से तीन सत्र खेले हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 66 मैचों में 20 गोल दागे हैं। उनका पिछला सीजन विशेष रूप से अच्छा रहा। इस दौरान उन्होंने 27 मैचों में 13 गोल किये। उन्हें पिछले सीजन में लीग का सर्वश्रेष्ठ अंडर-23 खिलाड़ी भी चुना गया था। कार्लोस के इन गोलों के कारण ही लेवांते को निचली लीग में जाने से बचा था। सत्र सीजन के आखिरी हफ्तों में उनके प्रदर्शन ने टीम को मजबूती मिली थी। इस स्ट्राइकर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए स्पेनिश ला लीगा के क्लब विल्लारियल और इंग्लैंड की प्रीमियर लीग के साथ ही कई बड़े क्लबों ने भी रुचि दिखायी थी।

पाक के अरशद नदीम लुसाने डायमंड लीग में नहीं उतरेंगे



लाहौर। पाकिस्तान के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम 21 अगस्त को रिवटजरलैंड के लुसाने में आयोजित होने वाली डायमंड लीग में नजर नहीं आयेंगे। अरशद ने इस लीग से अपना नाम वापस ले लिया है। अरशद ने वै फैसला आगामी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियाई खेलों के लिए अपनी तैयारियों पर ध्यान देने के लिए लिया है। अरशद का कहना है कि वह अब दक्षिण अफ्रीका में एक

विशेष प्रशिक्षण शिविर में भाग लेकर अपनी शारीरिक और तकनीकी क्षमताओं को बेहतर बनाने पर काम करेंगे। यह कदम उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि उनका लक्ष्य इन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाकिस्तान को जीत दिलाना है। नदीम राइटमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप

में रजत पदक विजेता हैं। अभी वह लाहौर में अभ्यास कर रहे हैं। उनके कोच रहे सलमान बट ने भी कहा है कि अरशद जल्द ही दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। दक्षिण अफ्रीका में, वह अपने विदेशी कोच टर्नियस लीबेनबर्ग और स्थानीय प्रशिक्षकों की देखरेख में कई हफ्तों तक गहन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस विशेष शिविर का उद्देश्य उनकी सहनशक्ति, ताकत और भाला फेंकने की तकनीक को और बेहतर बनाना है, ताकि वे आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। कोच सलमान बट ने बताया कि डायमंड लीग जैसे बड़े आयोजनों से हटना एक सची-समझी रणनीति का हिस्सा है। उनका पूरा ध्यान एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप की तैयारी पर है। हम चाहते हैं कि वह इन महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हों, और इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है जो उन्हें दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा।

कारोबार

शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी; सेंसेक्स 300 अंक टूटा, निफ्टी 24,350 से नीचे

नई दिल्ली। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को झटका लगा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में खुले। कच्चे तेल की कीमतें स्थिर होने के बावजूद बाजार सीमित दायरे में रहा। सेंसेक्स करीब 300 अंक गिरकर 77,800.37 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 65.85 अंक की गिरावट के साथ 24,330.00 के स्तर पर आ गया। यह गिरावट बाजार में निवेशकों की चिंता को दर्शाती है। ट्रेड और हिंडाल्को जैसी कंपनियों के शेयरों में 2 फीसदी की बड़ी गिरावट देखी गई। बाजार

विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक संकेतों का भी असर भारतीय बाजार पर पड़ा।
क्या रही सेंसेक्स और निफ्टी की स्थिति?
शुक्रवार को सेंसेक्स 279.59 अंक यानी 0.35 फीसदी की गिरावट के साथ 77,800.37 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 65.85 अंक या 0.27 फीसदी की गिरावट आई। यह 24,330.00 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। दोनों प्रमुख सूचकांक लगातार सीमित दायरे में बने हुए हैं। वैश्विक बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। टोक्यो समय



अनुसार सुबह 11:47 बजे एसएंडपी 500 प्यूचर्स में मामूली बदलाव आया। जापान का टॉपिक्स 0.7

फीसदी की वृद्धि के साथ बंद हुआ। वहीं, ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एसएसक्स 200 और हांगकांग का

हेंग सेंग क्रमशः 0.8 फीसदी और 0.7 फीसदी नीचे गिरे। शंघाई कंपोजिट में भी 0.2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जबकि यूरो स्टॉक्स 50 प्यूचर्स 0.3 फीसदी बढ़ा।
डॉलर इंडेक्स 99.9 के करीब, फेडरल रिजर्व की दर वृद्धि की उम्मीदें घटीं
डॉलर इंडेक्स 7 अगस्त को 99.9 के आसपास कारोबार कर रहा था। अमेरिकी मुद्रास्फीति के नरम आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व की सितंबर में दर वृद्धि की उम्मीदों को कम कर दिया। जुलाई में अमेरिकी उत्पादक कीमतें अपरिवर्तित रहीं।

यह 5 अगस्त की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट के बाद हुआ। इससे व्यापक मुद्रास्फीति दबाव सीमित होने का संकेत मिला। बाजार अब सितंबर में 25 आधार अंक की वृद्धि की करीब 35 फीसदी संभावना जता रहे हैं। यह 31 जुलाई को 55 फीसदी से कम है। मुद्रास्फीति के नरम पड़ने से पश्चिम एशिया संघर्ष और उच्च ऊर्जा लागत का प्रभाव कम होने का संकेत मिलता है। फिर भी, हार्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के संभावित समझौते पर अनिश्चितता मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए जोखिम बनी हुई है।

जेपी एसोसिएट्स के बाद अदाणी ग्रुप ने खरीदी एक और कंपनी

नई दिल्ली। देश का अरबपति कारोबारी घराना अदाणी समूह तेजी अपने बिजनेस का विस्तार कर रहा है और कंपनियों का अधिग्रहण कर रहा है। जेपी एसोसिएट्स के बाद गौतम अदाणी की अगुवाई वाली अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।



रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने पाथ हाईवेज एलएलपी के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 91.34 करोड़ रुपये की डील अदाणी एंटरप्राइजेज द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि यह अधिग्रहण 91.34 करोड़ रुपये में किया गया है। इस सौदे के

तहत, अदाणी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने 99.99% और अदाणी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने 0.01% हिस्सेदारी खरीदी है। यह हिस्सेदारी 'प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल्स हाईवे (इंडिया) लिमिटेड' और 'श्रीमती नीति अग्रवाल' से खरीदी गई है। कंपनी ने बताया

3 बड़े प्रोजेक्ट पर होगा कंट्रोल

कि यह अधिग्रहण रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास उद्योग में अपने फुलप्रिंट बढ़ाने की रणनीति के अनुरूप है। पाथ हाईवेज एलएलपी की स्थापना 13 दिसंबर, 2018 को हुई थी और यह मुख्य रूप से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों के लिए एक निवेश होल्डिंग वाहन के रूप में कार्य करती है।

इस अधिग्रहण का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अदाणी ग्रुप का अब तीन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर नियंत्रण बढ़ जाएगा। इस डील से पहले, अडांनी रोड ट्रांसपोर्ट और पाथ हाईवेज मिलकर इन प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी रखते थे। अब अधिग्रहण के बाद, अदाणी रोड

ट्रांसपोर्ट की निम्नलिखित कंपनियों में 99.99% हिस्सेदारी हो जाएगी। इनमें मंचेरियल रैप्लेवेबाड़ा रोड लिमिटेड, सूर्यापेट खम्मम रोड लिमिटेड, और बिलासपुर पथरापाली रोड लिमिटेड शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले अदाणी ग्रुप ने लंबी चली प्रक्रिया के बाद दिवालिया समूह जेपी एसोसिएट्स को खरीदा था। अदाणी समूह ने दिवालिया प्रक्रिया के तहत कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का अधिग्रहण 14,535 करोड़ में किया था। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद बेंच ने मार्च 2026 में इस डील को अपनी मंजूरी दी थी।

नई दिल्ली। कुमार मंगलम बिड़ला की सबसे बड़ी कंपनी पर बड़ा अपडेट आया है। भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के प्रमोटरों में से एक, पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को खुले बाजार के लेनदेन के माध्यम से कंपनी में लगभग 1 प्रतिशत हिस्सेदारी 2,896 करोड़ रुपये में बेच दी। बीएसई पर उपलब्ध ब्लॉक डील डेटा के अनुसार, पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुंबई स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड में 0.85 प्रतिशत हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 लाख इक्विटी शेयर बेचे। शेयरों को 18 किस्तों में औसतन 11,585 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बेचा गया, जिससे कुल सौदे का मूल्य 2,896.25 करोड़ रुपये हो गया।

हिस्सेदारी की बिक्री के बाद, पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हिस्सेदारी 1.5 प्रतिशत से घटकर लगभग 1 प्रतिशत हो गई है, जबकि प्रमोटरों और प्रमोटर समूह की संस्थाओं की संयुक्त हिस्सेदारी 59.33 प्रतिशत से घटकर 58.49 प्रतिशत हो गई है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड (एमएफ), आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ, कोटक महिंद्रा एमएफ, नेशनल पेंशन इंश्योरेंस फंड, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एमएफ और केनरा एचएसबीसी ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस सहित कई घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इस लेनदेन में भाग लिया। विदेशी निवेशकों जेपी मॉर्गन और नॉर्वे के सॉर्गेरेन वेल्थ फंड, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने भी शेयर खरीदे।

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, खरीदारों ने समान संख्या में शेयर समान कीमत पर खरीदे। अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर बीएसई पर लगभग 1 प्रतिशत गिरकर 11,750 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। यह हिस्सेदारी बिक्री अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और पारेषण में लगी कंपनी सोलारिस होराइन एनर्जी में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के समझौतों की घोषणा के एक दिन बाद हुई है।
अल्ट्राटेक सीमेंट का रिजल्ट कैसा रहा?
पिछले महीने, अल्ट्राटेक सीमेंट ने वित्त वर्ष 2027 की जून तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 17.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2,603.72 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया।



शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले

1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी की याद में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की याद दिलाता है और हर नागरिक को एकता, देशभक्ति और लोकतंत्र के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। इस मौके पर स्कूल, कॉलेज और संस्थान भाषण प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ‘शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा’ – जगदंबा प्रसाद मिश्रा की ये दमदार देशभक्ति वाली लाइनें आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती हैं। ये लाइनें देशभक्ति की भावना को पूरी तरह से दिखती हैं। 15 अगस्त 1947 को अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान की वजह से भारत आजाद हुआ था। हर साल यह दिन हमें आजादी की कीमत, राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। स्वतंत्रता दिवस देश के लिए उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का एक शानदार तरीका है, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।’ ये लाइनें बताती हैं कि हम 1947 में ऐतिहासिक उपलब्धि अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान से संभव हो पाई थी, जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। इस खास दिन पर हम महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और कई अन्य बहादुर देशभक्तों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके बलिदानों ने हमें वह आजादी दिलाई है।

नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियां
स्वतंत्रता दिवस केवल हमारे देश के इतिहास का उत्सव नहीं है, यह एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों की याद भी दिलाता है। आजादी के साथ कुछ कर्तव्य भी आते हैं। हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए, देश की एकता और विविधता की रक्षा करनी चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और ईमानदारी, कड़ी मेहनत व दयाभाव के साथ भारत की प्रगति में योगदान देना चाहिए। छात्रों के रूप में हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, अपने शिक्षकों और माता-पिता का सम्मान करके, दूसरों की मदद करके और जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकते हैं। दया, अनुशासन और समर्पण के छोटे-छोटे कार्य एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए इस अवसर पर हम अपने शहीदों के बलिदानों को याद करें और भारत को शांति, समानता और प्रगति वाला देश बनाने के अपने संकल्प को दोहराएं। हम सब मिलकर उस भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसी दिन 1947 में ब्रिटिश शासन के बाद देश को आजादी मिली थी। इस मौके पर स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और समुदायों में झंडा फहराने के समारोह, देशभक्तिपूर्ण भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है, जो हर नागरिक को आजादी, एकता, लोकतंत्र के मूल्यों और देश की प्रगति में योगदान देने की जिम्मेदारी की याद दिलाता है।



15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर जरूर करें ये काम

देशभक्ति के साथ ऐसे मनाएं आजादी का पर्व

स्वतंत्रता दिवस या 15 अगस्त सिर्फ़ एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं, बल्कि उन शहीदों को याद करने और उनके बलिदान का सम्मान करने का दिन है, जिन्होंने हमें यह आजादी दी। इस दिन को सार्थक बनाने के लिए हमें कुछ खास कार्य जरूर करने चाहिए, जिससे हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना और भी गहरी हो सके।

राष्ट्रगान गाएं और तिरंगा फहराएं
सुबह उठकर अपने घर या कॉलोनी में ध्वजारोहण करें। इस दौरान पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगान गाएं। यह हमारे देश के गौरव का प्रतीक है और हमें हमारे संविधान और संप्रभुता की याद दिलाता है। सुनिश्चित करें कि ‘भारतीय झंडा संहिता’ के नियमों का पालन करते हुए तिरंगा सही तरीके से फहराया जाए और शाम को सम्मानपूर्वक उतारा जाए।

शहीदों को श्रद्धांजलि दें
आजादी की लड़ाई में अपनी जान कुर्बान करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें। आप उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं, दो मिन्ट का मोन रख सकते हैं या उनकी जीवनी पढ़कर उनके संघर्षों को नमन कर सकते हैं। बच्चों और युवाओं को भी उनके बलिदान और योगदान से अवश्य अवगत कराएं।

देशभक्ति की फिल्में और गाने देखें/सुनें
परिवार और बच्चों के साथ बैठकर देशभक्ति से भरी फिल्में (जैसे सरदार उधम, शेरशाह, भगत सिंह) देखें या प्रेरणादायक देशभक्ति गीत सुनें। ऐसा करने से हमारे अंदर देश के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना मजबूत होती है और यह नई पीढ़ी को हमारे इतिहास व वीरों की गाथाओं से जोड़ने का एक बेहतरीन जरिया है।

समाज सेवा का संकल्प लें
स्वतंत्रता का असली अर्थ तब है, जब हमारा समाज स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध हो। इस दिन गरीबों को भोजन कराने, अनाथ बच्चों को पठन-सामग्री बांटने या वृद्धाश्रम में समय बिताने जैसे सामाजिक कार्य करें। इसके साथ ही ‘मेड इन इंडिया’ (स्वदेशी) वस्तुओं को प्राथमिकता देने का संकल्प लें।

देश की प्रगति में योगदान का वादा करें
स्वतंत्रता दिवस पर खुद से यह वादा करें कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की प्रगति में योगदान देंगे। यह वादा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने, दैफिक नियमों का पालन करने और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने का हो सकता है। साथ ही रवतदान, अंगदान जागरुकता या पौधारोपण जैसे अभियानों में बढ़-चढ़कर भाग लें। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाएं।

स्वतंत्र भारत की घोषणा

15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउन्ट बैटन और एडविना 14 अगस्त 1947 को रात को 11.00 बजे संघटक सभा द्वारा भारत की स्वतंत्रता को मनाने की एक बैठक आरंभ हुई, जिसमें अधिकार प्रदान किए जा रहे थे। जैसे ही घड़ी में रात के 12.00 बजे भारत को आजादी मिल गई और भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। तत्कालीन स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण नियति के साथ भेंट दिया।

जैसे ही मध्य रात्रि हुई, और जब दुनिया सो रही थी, भारत जाग रहा होगा और अपनी आजादी की ओर बढ़ेगा। एक ऐसा पल आता है जो इतिहास में दुर्लभ है, जब हम पुराने युग से नए युग की ओर जाते हैं... क्या हम इस अवसर का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त बहादुर और बुद्धिमान हैं और हम भविष्य की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं

– पंडित जवाहरलाल नेहरू

इसके बाद तिरंगा झण्डा फहराया गया और लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गान गाया गया।

आजादी के इस पावन पर्व को यादगार बनाने के लिए कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसके देखभाल की जिम्मेदारी लें। एक स्वच्छ, हरा-भरा और प्रदूषण-मुक्त भारत ही हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा।

स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक या संग्रहालय जाएं
यदि आपके शहर या आसपास कोई ऐतिहासिक स्थल, स्वतंत्रता सेनानियों का स्मारक या संग्रहालय है, तो परिवार के साथ वहां जरूर जाएं। इससे इतिहास की किताबों में पड़े पन्ने जीवंत हो उठते हैं और देश की आजादी के मोल का वास्तविक अहसास होता है।

सोशल मीडिया पर सकारात्मकता और राष्ट्रप्रेम फैलाएं

आज के डिजिटल युग में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस का सही इस्तेमाल करें। भ्रामक या नफरत फैलाने वाली खबरों के बजाय देश की उपलब्धियों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों और सेना के जवानों की प्रेरक कहानियां शेयर करें। अपने तिरंगे के साथ गर्व से फोटो या संदेश साझा करें।

भारतीय संस्कृति और भाषाओं का सम्मान करें
भारत की विविधता ही हमारी असली ताकत है। इस दिन देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, वेशभूषा और खान-पान के बारे में जानें। अपनी मातृभाषा के साथ-साथ देश की अन्य भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करने का संकल्प लें।

अधिकारों के साथ-साथ अपने ‘मौलिक कर्तव्यों’ को समझें

स्वतंत्रता हमें अधिकार तो देती है, लेकिन इसके साथ ही नागरिकों के कुछ ‘मौलिक कर्तव्य’ भी हैं। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, जल बचाना, महिलाओं का सम्मान करना और समाज में भाईचारा कायम रखना भी देशभक्ति का ही एक रूप है।

आन-बान-शान के साथ मनाएं 15 अगस्त, पीएम ने देशवासियों से की ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में शामिल होने की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस गर्व और सम्मान के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लें। उन्होंने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और स्वतंत्रता दिवस के जश्न में उत्साह के साथ शामिल होने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा, ‘हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा, हर मन तिरंगा।’ उन्होंने लोगों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने और स्वतंत्रता दिवस के जश्न में उत्साह के साथ शामिल होने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि 15 अगस्त को ऐतिहासिक लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गाया जाएगा और इस कार्यक्रम की थीम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवा शक्ति का योगदान होगी। भारत 15 अगस्त को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली के लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान युवाओं की उपलब्धियों और योगदान को रेखांकित करने की योजना जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन से पहले ही तय की जा चुकी थी। उन्होंने कहा, ‘विकसित भारत की दिशा में हमारी यात्रा में युवा बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि वे इसमें योगदान भी देंगे और उम्मीद है कि इसका लाभ भी उठाएंगे। यही एकमात्र वजह है।’

रक्षा सचिव के अनुसार, प्रधानमंत्री के लाल किले पहुंचने पर वंदे मातरम् का गायन होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र के नाम पारंपरिक संबोधन देंगे। भारतीय वायुसेना का एमआई-17 हेलीकॉप्टर वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बैनर लेकर लाल किले के ऊपर से उड़ान भरेगा और वहां मौजूद लोगों पर फूल बरसाएगा।

स्वतंत्रता दिवस पर घर पर ही फहरा रहे हैं तिरंगा, भूलकर भी न करें ये गलतियां

भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार है. पिछले साल की तरह इस साल भी भारत सरकार ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने की अपील की है. हर घर तिरंगा अभियान के तहत पीएम मोदी ने सभी से अपने घर की छत, बालकनी पर तिरंग फहराने की अपील की है. साथ ही इसकी फोटो शेयर करनी की भी अपील की है. यदि आप भी हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा ले रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है.

राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 की धारा 3.23 राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन के दुरुपयोग के बारे में बताती है. घर पर तिरंगा फहराने के लिए कुछ खास नियम होते हैं. इसे सबसे पहला होता है तिरंगा का साइज. झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए. वहीं, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3.2 होना चाहिए. अशोक चक्र में 24 तीलियां होनी चाहिए. नियमों के बदलने के बाद आप इसे 24 घंटे और 365 दिनों तक बिना रोकटोक लगा सकते हैं.

घर पर यदि तिरंगा फहरा रहे हैं तो फटा और मेला तिरंगा न फहराएं. यदि किसी कारण आपका तिरंगा फटा जाता है तो उसे एकांत में जाकर नष्ट कर दें. इसके अलावा तिरंगे के ऊपर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए. साथ ही इस पर कुछ भी छपा नहीं होना चाहिए. यदि आपके घर पर तिरंगे के अलावा कोई अन्य ध्वज भी फहराया हुआ है तो ध्यान रखें कि वह तिरंगे से ऊंचा न रखा जाए. साथ ही ये तिरंगे के बराबर भी न हो. सबसे अहम बात स्वतंत्रता दिवस के बाद अपनी छत या बालकनी से तिरंगे को उतार दें और तह करके रख दें. याद रखें कि किसी भी स्थित में झंडा जमीन से नहीं छूना चाहिए. झंडे के किसी भी हिस्से को यदि जलाया जाता है या उसे नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसके लिए तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है.

15 अगस्त पर लाल किले से गूंजेगा वंदे मातरम...

देश इस साल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे. इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य फोकस युवा शक्ति 2047 तक विकसित भारत की यात्रा पर रहेगा. इस साल वंदे मातरम् के 150 साल भी पूरे हो रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम् का सामूहिक गायन होगा. लाल किले की प्राचीर के दोनों

तरफ फूलों की सजावट में भी वंदे मातरम् की थीम दिखाई देगी. लाल किले के सामने ज्ञान पथ पर NCC और मेरा युवा भारत के करीब 2500 छात्र-छात्राएं और स्वयंसेवक वंदे मातरम् की आकृति बनाएंगे. प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट और मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक राष्ट्रगीत वंदे मातरम् का गायन करेंगे. इसके बाद राष्ट्रगान होगा. राष्ट्रगीत के दौरान सभी लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़े होने के लिए कहा जाएगा. भारतीय वायुसेना का हेलिकॉप्टर वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने की याद में बैनर लेकर लाल किले के ऊपर से उड़ान भरेगा और वहां मौजूद लोगों पर पुष्पवर्षा करेगा.

